



MAHARASHTRA NATIONAL LAW UNIVERSITY NAGPUR

News Clippings

January – December 2021



तीन विश्वविद्यालयों के लिए अलग बिजली उपकेंद्र लगाएंगे : राऊत

नागपुर। 15 जनवरी। लोस सेवा

राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत ने कहा है कि वर्धा मार्ग पर स्थित वारंगा में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, कवि कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, आईआईटी अभिमत विश्वविद्यालय परिसर विकसित हो रहा है। यहां पर भविष्य की बिजली की मांग को ध्यान में रखते हुए महावितरण की ओर से इन विश्वविद्यालयों के लिए अलग बिजली उपकेंद्र लगाए जाएंगे।

शुक्रवार को पालक मंत्री नितिन राऊत ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय



हार्वेस्टिंग के माध्यम से यहां पर बारिश के पानी को परिसर में बनाए गए तालाबों में ही इकट्ठा किया जाएगा। इससे परिसर में पानी की किल्लत नहीं होगी। बिजली की बचत करने की मंशा

परिसर में जायजा बैठक लेकर इस काम का जायजा लिया। इस समय रेन वॉटर

से परिसर में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी जानकारी विश्वविद्यालय की ओर से दी गई।

नितिन राऊत ने इस समय कहा कि विवि में पढ़ने आने वाले विद्यार्थियों को किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। इस समय विभागीय आयुक्त संजीवकुमार, महावितरण के नागपुर परिक्षेत्र के प्रभारी प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, अधीक्षक अभियंता अमित परांजपे, कार्यकारी अभियंता प्रफुल्ल लांडे तथा विधि विश्वविद्यालय के अधिकारी उपस्थित थे।

3 विद्यापीठों के लिए स्वतंत्र बिजली सब स्टेशन बनेंगे

ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत ने किया निरीक्षण



भास्कर संवाददाता | नागपुर. वर्धा रोड पर वारंगा में राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, कवि कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, आईआईआईटी अभिमत विद्यापीठ परिसर का काम चल रहा है। भविष्य में बढ़ती बिजली की मांग व इन तीन विद्यापीठों को अबाधित बिजली आपूर्ति के लिए तीन स्वतंत्र सब स्टेशन (उपकेंद्र) बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत ने दिए हैं। डॉ. राऊत ने विधि विद्यापीठ परिसर में जाकर वहां जारी निर्माणकार्य का निरीक्षण भी किया। उनके साथ महावितरण के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

परिसर में होगा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल

डॉ. राऊत ने राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक कर जारी काम-काज की समीक्षा की। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग से बारिश का पानी परिसर में बनाए जाने वाले तालाब में संगृहित होगा, जिससे यहां पानी की किल्लत नहीं होगी। बिजली की बचत हो, इसलिए परिसर में बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा।

विद्यार्थियों को अच्छी सुविधा दी जाएगी

डॉ. राऊत ने स्पष्ट किया कि, विद्यार्थियों को विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करते समय कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्हें अच्छी सुविधा दी जाएगी। इस दौरान विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, महावितरण नागपुर परिक्षेत्र के प्रभारी प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, अधीक्षक अभियंता अमित परांजपे, कार्यकारी अभियंता प्रफुल लांडे व विधि विद्यापीठ के अधिकारी उपस्थित थे।



विद्यापीठासाठी स्वतंत्र बीज उपकेंद्र करणार ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची माहिती

लोकसत्ता प्रतिनिधी

नागपूर : वर्धा रोडवरील वारंगा येथे राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, कवी कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, आयआयआयटी अभिमत विद्यापीठांची भविष्यातील विजेची मागणी लक्षात घेता महावितरणकडून या विद्यापीठांना अखंडित आणि दर्जेदार वीजपुरवठा मिळावा, यासाठी स्वतंत्र बीज उपकेंद्राचा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत दिल्या.

त्यांनी शुक्रवारी राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ परिसरात आढावा बैठक घेऊन सुरू असलेल्या कामाची पाहणी केली. यावेळी 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'च्या माध्यमातून पावसाचे पाणी परिसरात निर्माण केलेल्या तलावात साठवण्यात येणार असल्याने

येथे पाण्याची समस्या राहणार नाही. तसेच विजेची बचत व्हावी यासाठी परिसरात मोठ्या प्रमाणात सौरऊर्जेचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती विद्यापीठाच्या वतीने सादरीकरण करताना देण्यात आली. विद्यापीठात विध्यार्थ्यांना कोणताही त्रास होता काम नये. त्यांना चांगल्या सुविधा देणे आपले कर्तव्य असल्याचे डॉ. नितीन राऊत यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी विभागीय आयुक्त संजीवकुमार, महावितरणचे नागपूर परिक्षेत्राचे प्रभारी प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, अधीक्षक अभियंता अमित परांजपे, कार्यकारी अभियंता प्रफुल्ल लांडे तसेच विधि विद्यापीठाचे अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.



तीन विद्यापीठांसाठी स्वतंत्र वीजकेंद्रे

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर

महावितरणकडून विद्यापीठांना अखंडित आणि दर्जेदार वीजपुरवठा मिळावा, याउद्देशाने स्वतंत्र वीज उपकेंद्रांचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी महावितरणला दिले.

वर्धा मार्गावरील वारंगा येथे होणारे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ, रामटेकचे कवी कालिदास संस्कृत विद्यापीठ आणि आयआयआयटी अभिमत विद्यापीठाच्या परिसरात हे उपकेंद्र स्थापन करण्यात येणार असून, या माध्यमातून या तिन्ही विद्यापीठांना अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासंबंधीच्या सर्व उपाययोजना तत्काळ करण्याच्या सूचना महावितरणला देण्यात आल्या आहेत. भविष्यातील विजेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन महावितरणकडून या विद्यापीठांना अखंडित आणि दर्जेदार



ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ परिसराला भेट देत वीज उपकेंद्राच्या कामाचा आढावा घेतला

वीजपुरवठा मिळावा यादृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याची माहिती आहे. यासंदर्भात राऊत यांनी राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या परिसराला भेट दिली व यासंदर्भातील कामाचा आढावा घेतला. यावेळी रेनवॉटर हार्वेस्टिंगच्या माध्यमातून पावसाचे पाणी परिसरात निर्माण केलेल्या तलावात साठविण्यात येणार असल्याने येथे पाण्याची समस्या राहणार नाही. तसेच विजेची बचत व्हावी, यासाठी परिसरात मोठ्या प्रमाणात सौरऊर्जेचा

वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती विद्यापीठाच्या वतीने सादरीकरण करतेवेळी देण्यात आली.

यावेळी विभागीय आयुक्त संजीवकुमार, महावितरणचे नागपूर परिक्षेत्राचे प्रभारी प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, मुख्य अभियंता दिलीप दोडके, अधीक्षक अभियंता अमित परांजपे, कार्यकारी अभियंता प्रफुल्ल लांडे तसेच विधी विद्यापीठाचे अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

नवभारत

पालक मंत्री राऊत ने दिए निर्देश, कार्य पूरा करने समिति का गठन

राविवि की इमारत का निर्माण जल्द पूरा करें

कार्यालय प्रतिनिधि

नागपुर. वारंगा स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की प्रशासकीय इमारत का काम अंतरराष्ट्रीय मानकोंनुसार गुणावत्तापूर्ण जल्द गति से पूरा करने के निर्देश पालक मंत्री डॉ. नितिन राऊत ने विश्वविद्यालय के प्रशासन को शुक्रवार को दिए. उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर की इमारत के निर्माण कार्य का मुआइना करने के बाद अधिकारी, विकासक और वास्तु विशारद के साथ जायजा बैठक ली. विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार, उप कुलपति विजेंद्र कुमार, विशेष कार्य अधिकारी प्रा. रमेश कुमार, कुलसचिव आशीष दीक्षित, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधीक्षक अभियंता विद्याधर सरदेशमुख, कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे, उपविभागीय अभियंता प्रशांत शंकरपुरे,



वास्तुविशारद परमजीतसिंह आहुजा, मनोज लद्धड़, महावितरण के मुख्य अभियंता डी. एल. दोडके, अधीक्षक अभियंता अमित परांजपे, बूटीबोरी के कार्यकारी अभियंता प्रफुल लांडे, एनएमआरडीए के कार्यकारी अभियंता राजेश मेघराजानी, राघवेंद्र चौरसिया और सुहास रंगारी सहित आदि उपस्थित थे. स्थानीय सभी इमारतों का निर्माण कार्य

करते समय पर्यावरण संवर्धन के सभी मानकों का पालन करने का आदेश भी पालक मंत्री ने दिया. इस परिसर में वृक्षारोपण करने का नियोजन करते वक्त तालाब, इमारत और सड़क के दोनों ओर सौंदर्यीकरण करने व उसके लिए मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की इमारत की तरह म्यूरल्स और शिल्पचित्रों पर पालक मंत्री ने जोर दिया.

हरित इमारत की तकनीक का इस्तेमाल

उन्होंने 31 मार्च तक आवश्यक तैयारी पूरी करने के लिए समिति गठित कर जिम्मेदारी निश्चित करने का आदेश भी दिया. 5 फरवरी को जायजा लेने के लिए वे आने वाले हैं. परिसर में आईआईआईटी, संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे बड़े शैक्षिक संस्था आने से बिजली की अखंडित आपूर्ति के लिए स्वतंत्र तथा समर्पित सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी महावितरण अधिकारियों को दिए. संग्रहालय में कानून क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करनेवाले विधि विशेषज्ञों तथा आकर्षक शिल्प, कलाकृति प्रदर्शित करने के निर्देश डॉ. राऊत ने विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए. विधि विश्वविद्यालय से संबंधित मुख्यमंत्री के साथ 9 जनवरी को बैठक हुई, जिसमें नई इमारत निर्माण कार्य का समावेश करने के लिए 164 करोड़ रुपयों का बजट और प्लान सहित राज्य सरकार को प्रस्ताव पेश करने का पत्र प्रशासन की ओर से विश्वविद्यालय को दिया गया. विश्वविद्यालय का प्रस्ताव 18 जनवरी को राज्य सरकार को भेजने की बात भी उन्होंने बताई. पानी को रिसाइकल कर उसका शुद्धीकरण करना और बिजली का इस्तेमाल करते हुए सौर ऊर्जा पर जोर देकर शून्य खर्च पर लाने की सूचना की. साइबर सुरक्षा, अग्निशामक दीवारें, डिजिटल पौडियम व स्मार्ट बोर्ड, वातानुकूलित विभाग, नागपुर के मौसम का अंदाज ध्यान में लेते हुए उच्च तकनीक से गर्मी का लोड कम करने, 5 लेवल का इन्सुलेशन, हरित इमारत की तकनीक का इस्तेमाल करने की सूचनाओं के साथ 31 मार्च तक प्रशासकीय इमारत के ब्लॉक का काम पूरा करने की सूचना पालक मंत्री ने दी. भविष्य में पानी की जरूरत को ध्यान रख जल संग्रहित करने के लिए उतनी ही क्षमता का तालाब विकसित करने, आसपास के स्टोरेज ट्रैक केंद्र को जोड़नेवाली पाइप लाइन पर जलसंग्रहण के लिए विशिष्ट पत्थर का उपयोग करने, 2 इमारतों को जोड़नेवाले स्काइब्रिज तथा निर्माण कार्य के दूसरे चरण में पुल, लाइब्रेरी और साथ ही वाईफाई भी उपलब्ध कराने की जानकारी यहां दी गई.

Law University contributes largely to development of national perspective: CJI Bobde

■ We need a generation that would be committed to the society, says CM Uddhav Thackeray

■ Academic building of Maharashtra National Law University at Nagpur inaugurated

■ Principal Correspondent

"JUDICIARY is a very important pillar of democracy. To strengthen it, good quality legal education is required and the National Law University here is playing an important role. The university will definitely make a significant

contribution to the development of national vision and character," said Chief Justice of India Sharad Bobde. He was speaking during inauguration of academic building of Maharashtra National Law University (MNLU) at Waranga on Wednesday.

The inauguration was done on virtual platform in presence of Chief Justice on India and Founder Chancellor of the University Sharad Bobde, Chief Minister Uddhav Thackeray, Union Minister of Transport Nitin Gadkari, Supreme Court Justice Bhushan Gavai, Chief Justice of Bombay High Court Dipankar Dutta, Energy Minister and Guardian Minister of Nagpur dis-



Chief Justice of India Sharad Bobde delivering the speech.

trict Dr Nitin Raut, Higher and Technical Education Minister Uday Samant and Leader of Opposition in State Assembly Devendra Fadnavis, Senior Administrative Judge of Nagpur Bench of Bombay High Court Justice Sunil Shukre; Vice-Chancellor of the University Prof Dr Vijendra Kumar and others.

The Chief Justice gave a brief overview of the creation of the University. Given the glorious tradition of the best jurists in the city of Nagpur, the people here wanted a National Law University. Expressing satisfaction that their dream is coming true today Justice Bobde said, "The academic building of the

university is a beautiful invention of modern architecture. The construction of classrooms in this building is world class. These classrooms are equipped with the latest technology."

Justice Bobde pointed out, "Construction of this building, which is of excellent quality and environment-friendly, fulfills the aspirations of the students." He mentioned the efforts made by Justice Bhushan Gavai and Mumbai High Court Chief Justice Dipankar Dutta for estab-

lishment of the university.

Announcing that Justice Bhushan Gavai would take the charge as Chancellor of MNLU, Chief Justice Sharad Bobde said, "The National Law University here is unique. This university will help to develop a national outlook. Because professors and students from all over the country will come and teach here. This university will go beyond the thought of regionalism and narrow



Justice Bhushan Gavai to be Chancellor of MNLU

(Contd on page 2)

Law University contributes largely to development of national perspective...

mindfulness and would create jurists with national character.

Chief Justice Sharad Bobde expressed confidence that the way MNLU is moving ahead, it would earn the level of Oxford-Harvard-Cambridge University. Another feature of this university is the inclusion of jurisprudence courses. Due to this, the rich knowledge tradition of this subject in India has been linked with the university. He also hoped that future generations would be thankful for the results.

Chief Minister Uddhav Thackeray said, "Maharashtra, which abides by the framework of law, has a long and exemplary tradition of justice. It was carried forward by judges like Ramshastri Prabhune. The role of the four pillars is important in a democracy. They give strong support to democracy." Chief Minister expressed the expectation that the university should create lawyers and jurists who are able to hold the roof of democracy."

"Just as the sculptor creates an idol by putting his heart into it, professors at the University of Law should play their roles and shape students. Dr Babasaheb Ambedkar took to the streets and fought for the common man. Accordingly, this institution should produce judges who would have commitment towards poor. The University of Law is a large institution that respects and

supports the field of justice. This greatness should be used by the smallest man, and it should become the best university in the world," hoped Uddhav Thackeray.

Stating that the university was set up with the objective of creating a world class university that would introduce qualitative change in the field of law, Nitin Gadkari said, "One of the pillars of a strong democracy is the judiciary. The University of Law will play an important role in establishing it."

Gadkari in his speech specially mentioned the contribution of Justice Vikas Sirpurkar, retired judge of Supreme Court and Justice Bhushan Gavai, Judge of Supreme Court in creation of MNLU.

Stating that the creation of this university is the moment of self-satisfaction, Justice Gavai said that the concept of Gurukul is being actualised by this university. The values required for democracy are reflected in this university. We have succeeded in completing most of the work in the last five years. Various departments of the government, including the Chief Justice and the then and present rulers, cooperated, added Justice Gavai.

C Ramesh Kumar, OSD (Academics and Construction) proposed a vote of thanks while Dr Ashish Dixit, Registrar gave introductory speech.

People have faith in judicial system: CJI Bobde



CJI Sharad Bobde, Supreme Court judge Justice Bhushan Gavai, CJ Dipankar Datta, Senior Administrative Judge Sunil Shukre and Justice Z A Haq releasing Marathi edition of the book 'Courts of India' at HC auditorium on Wednesday.



DELHI CONFIDENTIAL



THE ABSENTEES

CHIEF JUSTICE of India S A Bobde inaugurated the Maharashtra National Law University on Nagpur on Wednesday. Keeping with Covid times, the rest of the dignitaries, including Supreme Court judge Bhushan Gavai, who is from the Nagpur bench of the Bombay High Court like the CJI, attended virtually. Curiously, two other Supreme Court judges, who are also from the Bombay High Court – justices A M Khanwilkar and D Y Chandrachud – were missed at the event. Those in legal circles noted that this was the second time that the two judges were absent at functions related to Bombay High Court. On March 26, when CJI Bobde inaugurated a bench of the Bombay High Court in Goa, while justice Gavai was present along with CJI-designate N V Ramana, both justices Khanwilkar and Chandrachud were not present.

Ambedkar worked to make Sanskrit official language: CJI

VIVEK DESHPANDE
NAGPUR, APRIL 14

CHIEF Justice of India S A Bobde on Wednesday claimed that the late B R Ambedkar had prepared a proposal to make Sanskrit the official language of India but the move did not succeed.

"I was wondering in which language should I speak, Marathi or English. This dilemma is being witnessed in our country for a

long time. I have seen this question cropping up frequently as to which language should the courts function in. We have High Courts with official language as English and Hindi. Some want Tamil, some others want Telugu. I want to humbly submit that nobody is paying attention to this subject. Dr Ambedkar, however, had anticipated this and had prepared a proposal. I don't know if that proposal was tabled. It had signatures of some mullahs, pandits and priests



Chief Justice S A Bobde

and of doctor Ambedkar himself. The proposal was that the official language of Union of India should

be Sanskrit," Justice Bobde said while addressing an event to mark the inauguration of the academic building of the Maharashtra National Law University at Nagpur.

"Ambedkar was of the opinion that Tamil won't be accepted in North India and Hindi won't be accepted in South India. But Sanskrit won't be opposed in either North India or South India. So he had made this proposal which did not succeed."

Justice Bobde said, "Ambedkar wasn't an expert in law only but was seized of what was going on socially and politically too. He knew what people wanted, what the poor wanted. That's why, I think, he had thought of this proposal. But finally English was made official language. So with your permission, this being the national law university, I will speak in English."

The CJI congratulated the NLU for introducing a course in "nyay

shastra", the ancient jurisprudence in Sanskrit. "The Indian judiciary draws its jurisprudence from Anglo-saxon model which is based on Aristotelian and Persian logic. When I read about nyay shastra, I found that it is not a bit inferior to the Aristotelian system. I see no reason that we should forsake, overlook and not benefit from the genius of our ancestors," Justice Bobde said.

FULL REPORT ON
www.indianexpress.com

राष्ट्रीय दृष्टिकोनासाठी विधी विद्यापीठाचे योगदान महत्त्वाचे

सरन्यायाधीश बोबडे : महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या
शैक्षणिक इमारतीचे उद्घाटन; न्या. भूषण गवई कुलपती होणार



लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : न्यायव्यवस्था हा लोकशाही व्यवस्थेचा अतिशय महत्त्वाचा स्तंभ आहे. तो मजबूत करण्यासाठी उत्तम दर्जाच्या विधी शिक्षणाची आवश्यकता असून येथील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ त्या दृष्टीने महत्त्वाचे आणि जागतिक दर्जाचे ठरणार आहे. राष्ट्रीय दृष्टिकोन आणि चारित्र्य विकसित करण्यासाठी हे विद्यापीठ निश्चितच महत्त्वाचे योगदान देईल, असा आशावाद देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी बुधवारी येथे व्यक्त केला.

शहराजवळच्या वारंगला येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक इमारतीचे उद्घाटन सरन्यायाधीश तथा या विद्यापीठाचे संस्थापक कुलपती शरद बोबडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते. दूरदृष्ट्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय भूपूष्ठ व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, ऊर्जामंत्री तथा पालकमंत्री नागपूर नितीन राऊत, ऊर्जा उच्च व तंत्रशिक्षण

महाराष्ट्राला न्यायदानाची आदर्श परंपरा लाभली : मुख्यमंत्री

कायद्याची चौकट पाळणाऱ्या महाराष्ट्राला न्यायदानाची मोठी आणि आदर्श परंपरा लाभली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यातही न्यायदानाची परंपरा अत्यंत आदर्शवत होती. रामशास्त्री प्रभुणेंसारख्या न्यायदात्यांनी ती पुढे चालवली. लोकशाहीत चार स्तंभांची भूमिका महत्त्वाची असते. त्यातून लोकशाहीला मजबूत आधार मिळत असतो, असे मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केले. लोकशाहीचे छत समर्थपणे तोलून धरणारे वकील, विधिज्ञ या विद्यापीठात घडावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मंत्री उदय सामंत, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्र, विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.डॉ. विजेंद्रकुमार आदी उपस्थित होते.

प्रारंभी विधी विद्यापीठाच्या निर्मितीमागचा ओझरता प्रवास सरन्यायाधीश बोबडे यांनी मांडला. न्यायमूर्ती भूषण गवई हे या विधी विद्यापीठाचे कुलपती असतील, असे त्यांनी जाहीर केले. या विद्यापीठातून राष्ट्रीय दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत होणार आहे. कारण देशभरातील प्राध्यापक आणि विद्यार्थी येथे अध्ययन-अध्यापन करणार आहेत. ऑक्सफर्ड- हॉर्वर्ड-केंब्रिज या विद्यापीठांच्या तोडीचे विद्यापीठ ठरणार आहे. न्यायशास्त्र अभ्यासक्रमाचा समावेश, हे या विद्यापीठाचे दुसरे वैशिष्ट्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गडकरी म्हणाले, विधी क्षेत्रात गुणात्मक बदल व्हावा, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विद्यापीठ उभारावे या उद्देशाने या विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. जागतिक दर्जाच्या सुविधा असलेले हे विद्यापीठ

असून यातून सर्वोत्कृष्ट न्यायाधीश व विधिज्ञ घडावेत, अशी अपेक्षा न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी व्यक्त केली. पालकमंत्री डॉ.राऊत यांनी विद्यापीठाची ही इमारत आणि परिसरातील इतर काम अतिशय कठीण अशा कोविड काळात करण्यात यश आल्याचे समाधान व्यक्त केले.

लोकशाही मूल्य प्रस्थापित होण्यासाठी कायद्याचे राज्य गरजेचे आहे. तर कायद्याच्या राज्यासाठी मजबूत न्यायव्यवस्था आवश्यक आहे त्यासाठी हे विद्यापीठ मोठे योगदान देईल, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. समतेची शिकवण देणाऱ्या दीक्षाभूमीच्या शहरात विधी विद्यापीठ स्थापन होणे हे आनंददायी असल्याचे मत न्यायमूर्ती सुनील शुक्र यांनी व्यक्त केले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या संदेशाचे वाचन यावेळी करण्यात आले.

प्रास्ताविक प्रा.आशिष सिंग यांनी प्रास्ताविक केले तर आभार प्रा. सी. रमेशकुमार यांनी मानले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती व्ही.एस. सिरपूरकर यांची यावेळी उपस्थिती होती.

'Quality law education must for strong judiciary'

■ Maharashtra National Law University campus inaugurated by CJI Bobde in Waranga village

LOKMAT NEWS NETWORK
NAGPUR, APRIL 14

The judiciary is a very important pillar of democratic set up. High quality law education is required to strengthen it. In view of this, the National Law University will prove to a very important milestone in the country. This university will definitely contribute in building national outlook and character, said Chief Justice of India Sharad Bobde.

The educational campus of Maharashtra National Law University was inaugurated at the hands of chancellor Sharad Bobde in Waranga on Wednesday. During online inauguration function, chief minister Uddhav Thackeray, Union minister for surface transport Nitin Gadkari, Justice Bhushan Gavai of Supreme Court,

Chief Justice of Bombay High Court Deepankar Datta, energy minister and guardian minister of district Nitin Raut, minister for higher and technical education Uday Samant, Leader of Opposition in Legislative Assembly Devendra Fadnavis, Justice Sunil Shukre of Nagpur Bench of Bombay High Court and university's vice-chancellor Dr Vijendra Kumar participated.

At the outset, Chief Justice of India Sharad Bobde spoke about the journey behind formation of the Law University and announced that Justice Bhushan Gavai will be the chancellor of university. CJI Bobde said, "This university will help in developing national outlook as teachers and students from all over country will



Chief Justice of India (CJI) Sharad Bobde addressing the law fraternity during the virtual inauguration of Maharashtra National Law University (MNLU) at Waranga village on Wednesday.

come here. This university will prove to be of global standard like Oxford, Harvard and Cambridge Universities. The inclusion of jurisprudence

course will be another speciality of this university."

Union minister Gadkari said, "This university has been formed with an objective of bringing qual-

itative change in legal field due to international level university."

Chief Justice Deepankar Datta said, "It is expected that better judges and legal experts will come of this university having world class amenities."

The guardian minister Raut said that there is satisfaction of completing university building and works of campus during difficult and coronavirus pandemic period.

Leader of Opposition Devendra Fadnavis said, "Rule of law is necessary for establishing values of democratic set-up. A strong judiciary is necessary for better rule of law. This university will contribute a lot in this direction." Justice Sunil Shukre said that it is a matter of pride that Law University has come up in the city having

Deekshabhoomi which gives message of equality. The message of deputy chief minister Ajit Pawar was also read out during the programme. Prof Ashish Singh made introductory remarks. Prof Rameshkumar proposed a vote of thanks. Retired Justice of Supreme Court V S Sirpurkar also attended the online programme.

'Maharashtra got ideal tradition of justice'

Chief minister Uddhav Thackeray said, "Maharashtra has a big and ideal tradition of giving justice to every criterion of law. The tradition of justice was very ideal during Swaraj of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Judges like Ramshastri Prabhune took this tradition forward. Roles of all pillars of democratic set-up are important."

संस्कृतला राष्ट्रभाषा करण्याचा बाबासाहेबांचा प्रस्ताव

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचे प्रतिपादन

लोकसत्ता प्रतिनिधी

नागपूर : देशातील काही उच्च न्यायालयांचे काम हे इंग्रजीतून तर



शरद बोबडे

काहींचे हिंदीमधून चालते. काहींना कामकाजाची भाषा तमिळ हवी आहे तर काहींना तेलगू हवी आहे. या अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या भाषांसाठी होत असलेल्या मागणीकडे कुणीही लक्ष देत नाही. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाची राष्ट्रभाषा ही संस्कृत असायला हवी असा प्रस्ताव दिला

होता. तोही मान्य न झाल्याने कार्यालयीन कामकाजाची नेमकी भाषा कुठली असावी हे द्वंद्व आजही सुरूच आहे, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केले.

उपराजधानीजवळच्या वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन सरन्यायाधीशांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री नितीन राऊत, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आदी ऑनलाईन तर कार्यक्रमस्थळी

सरन्यायाधीश जयंतीला पुण्यतिथी म्हणाले...

भाषणाला सुरुवात करत असताना सरन्यायाधीश बोबडे यांनी 'आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुण्यतिथीनिमित्त मला एक प्रसंग आठवला', असे विधान केले. त्यामुळे उपस्थितांमध्ये कुजबूज सुरू झाली. कारण, १४ एप्रिल रोजी बाबासाहेबांची जयंती असते, पुण्यतिथी नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य

'न्यायमूर्ती घडवणारे मूर्तिकार महत्वाचे'

विधि विद्यापीठाचे शिक्षक हे मूर्तिकार आहेत. न्यायमूर्ती घडवणारे हे मूर्तिकार हे फार महत्वाचे आहेत. त्यामुळे तुम्ही जीव ओतून शिकवले पाहिजे. कारण देशाचे, लोकशाहीचे छत्र समर्थपणे तोलून धरणारे वकील, विधिज्ञ या ठिकाणी घडतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. बाबासाहेबांनी सामान्यांसाठी रस्त्यावर उतरून लढाई लढली. त्यामुळे या संस्थेतून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग छोट्यातल्या छोट्या माणसांसाठी कसा होईल याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे

न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे उपस्थित होते. सरन्यायाधीश पुढे म्हणाले की,

देशाचा सरन्यायाधीश म्हणून देशातील अन्य न्यायालयांचे निवेदन करताना न्यायालयाची नेमकी भाषा कुठली असावी हा प्रश्न पडतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाची राष्ट्रभाषा ही संस्कृत राहायला हवी असा प्रस्ताव दिला होता. ज्यावर अनेक विद्यार्थी आणि पंडितांचीही स्वाक्षरी होती. कारण, उत्तर भारतात तामिळला तर दक्षिण भारतात हिंदीला विरोध होऊ शकतो हे त्यांना माहिती होते. त्यामुळे त्यांनी संस्कृतचा प्रस्ताव दिला होता. बाबासाहेब हे केवळ कायदेपंडितच नव्हते तर त्यांना समाजाचे, राजकारणाचे आणि येथील गोरगरिबांच्या प्रश्नांचीही जाण होती.

या सर्वांचा विचार करूनच त्यांनी हा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, तो मान्य झाला नाही, अशी खंत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय ओळख मिळवून देणाऱ्या विधि विद्यापीठात देशाच्या विविध भागातील विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावा उच्च दर्जाचे न्यायाधीश आणि अधिवक्ता येथे घडावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. शरद बोबडे हे विधि विद्यापीठ उभारणारे खरे वास्तुविशारद आहेत, अशा शब्दात गडकरींनी त्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी कुलगुरू विजेंद्र कुमार, विशेष कार्य अधिकारी प्रा. रमेश कुमार, कुलसचिव आशीष दीक्षित उपस्थित होते.



संस्कृत ही राष्ट्रभाषा असावी; बाबासाहेबांचा प्रस्ताव होता !

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर

'न्यायालयाच्या कामकाजाची भाषा कोणती असावी, यावर वारंवार चर्चा होत असते. उच्च न्यायालयांच्या कामकाजासाठी वेगवेगळ्या भाषांची मागणी देशातील विविध प्रांतांमध्ये होत असते. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संस्कृत ही भारताची राष्ट्रभाषा असावी, असा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, तो मान्य होऊ शकला नाही', अशी माहिती सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांनी बुधवारी येथे दिली.



नागपूरजवळील वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी सरन्यायाधीश बोलत होते. बुधवारी न्या. बोबडे यांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत ऑनलाइन स्वरूपात उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपाकर दत्ता, उच्च

नागपूरजवळील वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी सरन्यायाधीश बोलत होते. बुधवारी न्या. बोबडे यांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत ऑनलाइन स्वरूपात उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपाकर दत्ता, उच्च

नागपूर खंडपीठाचे उपस्थित होते. डॉ. आंबेडकर यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला अनेक तज्ज्ञांचे

सरन्यायाधीशांची माहिती; विधी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक इमारतीचे उद्घाटन



उद्घाटन कार्यक्रमात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे.

नागपूर खंडपीठाचे उपस्थित होते. डॉ. आंबेडकर यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला अनेक तज्ज्ञांचे

समर्थन होते. उत्तर भारतात तमिळनाडू तर दक्षिण भारतात हिंदीला विरोध होऊ शकतो, याची जाणीव त्यांना होती. सामाजिक, राजकीय आणि गोरगरिबांच्या परिस्थितीची जाण त्यांना होती. सर्वकष विचार करून त्यांनी हा प्रस्ताव दिला होता. त्याकरिता त्यांनी विविध धर्मातील प्रमुखांशी चर्चाही केली होती. मात्र, हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.

चांगल्या न्यायव्यवस्थेसाठी उत्तम न्यायशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचे पाठबळ असणे गरजेचे आहे. देशभरातील विद्यापीठांनी या विद्यापीठात प्रवेश घ्यावा आणि उत्तम दर्जाचे न्यायाधीश आणि अधिवक्ता येथून तयार व्हावेत,

विधी विद्यापीठातील शिक्षक महत्त्वाचे मूर्तिकार !

'सरकार कुणाचेही असो किंवा मुख्यमंत्री कुणीही असो, न्यायव्यवस्थेला साहाय्यभूत ठरणाऱ्या संस्थांना मदत करण्यात राज्य सरकार कुचराई करणार नाही. न्यायमूर्ती आणि वकील निर्माण करणारे विधी विद्यापीठातील शिक्षक हे महत्त्वाचे मूर्तिकार आहेत. या संस्थेतून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी लहानात लहान माणसासाठी आपल्या ज्ञानाचा कसा उपयोग होईल याचा विचार करावा', असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

अशी अपेक्षाही सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केली.

'सरन्यायाधीश बोबडे हे या प्रकल्पाचे यशस्वी आर्किटेक्ट आहेत. निवृत्त न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकर, विद्यमान न्यायमूर्ती भूषण गवई तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे', असे गडकरी म्हणाले. विधी विद्यापीठाची अत्यंत कमी कालावधीत उभारणी करण्यात बोबडे यांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. हे विद्यापीठ

भारतीय न्यायव्यवस्थेसाठी उत्तम मानव संसाधने निर्माण करेल अशी आशा आहे, असे फडणवीस म्हणाले. औरंगाबाद आणि मुंबई येथेही नागपूरप्रमाणे विधी विद्यापीठ संकुलाचे निर्माण करण्याचा मानस असल्याचे सामंत म्हणाले. पालकमंत्री नितीन राऊत तसेच इतर न्यायमूर्तींनीदेखील यावेळी मनोगत व्यक्त केले. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजेंदर कुमार यांनी प्रास्ताविक केले.

देश को उत्कृष्ट जज और वकील देगा विधि विवि : न्या. बोबडे

भास्कर प्रतिनिधि | नागपुर. लोकतंत्र के चार स्तंभों में से एक न्यायपालिका को सशक्त करने के लिए अच्छी विधि शिक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी गई थी। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील से लेकर न्यायपालिका और राजनीति के अनेक व्यक्तियों ने इसके विकास में योगदान दिया। अब यह विवि देश को बेहतर परिणाम देने के लिए तैयार है।

न्यायशास्त्र पढ़ाएंगे

देश के मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे ने बुधवार को महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एमएनएलयू) नागपुर की नई एकेडमिक बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विचार रखे। उन्होंने कहा कि इस विवि में विद्यार्थियों को सीधे न्यायाधीश बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। पाठ्यक्रम में ही उन्हें कोर्ट रूम अनुभव, जजों के साथ समय व्यतीत करने और अन्य प्रकार का प्रशिक्षण मिलेगा। इससे पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वे जज बनने के लिए पात्र हो जाएंगे। प्राचीन भारतीय ज्ञान पर निर्भर न्यायशास्त्र नामक पाठ्यक्रम भी कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ मिल कर शुरू किया गया है। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय देश को बेहतर जज और वकील प्रदान करेगा।

गरीबों को भी मिले कानूनी मदद

प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संबोधन में विद्यार्थियों से कहा कि विधि विवि से शिक्षा लेने के बाद विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वे अपने ज्ञान का फायदा समाज के आर्थिक



रूप से कमजोर तबकों को भी प्रदान करें। उन्हें भी बेहतर कानूनी मदद का अधिकार है। महंगी फीस के कारण वे इससे वंचित नहीं रहने चाहिए। जिस

प्रकार एक मूर्तिकार प्राण फूंक कर गणेश व दुर्गा की प्रतिमा बनाता है, ऐसे ही शिक्षकों को पूर्ण समर्पण भाव से भविष्य के बेहतर जज और वकील तैयार करने हैं। विवि को राज्य सरकार हर संभव मदद करेगी।

इन्होंने रखे विचार : कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई ने कहा कि विवि की निर्मिति निजी सार्थकता का ही एक क्षण है। असल मायनों में गुरुकुल की संकल्पना इस विवि के माध्यम से साकार हो रही है। इस दौरान ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराते हुए केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी ने कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का ही एक मजबूत स्तंभ है। विधि विवि इसे और मजबूत करने में सहकार्य करेगा। कार्यक्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता, प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत, नागपुर जिले के पालकमंत्री नितीन राऊत, विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस और नागपुर खंडपीठ के प्रशासकीय न्या. सुनील शुक्ले ने भी विचार व्यक्त किए। प्रस्तावना विवि कुलगुरु डॉ. विजेंद्र कुमार ने रखी। विवि शिक्षकों, विद्यार्थियों और पालकों के लिए कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया था।

न्या. गवई बने विवि कुलपति

न्या. बोबडे ने संबोधन में न्या. भूषण गवई को विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में घोषित किया। 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले न्या. बोबडे इस विवि के पहले कुलपति हैं। उनके बाद न्या. गवई यह जिम्मेदारी संभालेंगे। न्या. बोबडे ने बताया कि 13 अप्रैल को उन्होंने न्या. गवई का बतौर कुलपति नामांकन कर दिया है।

उद्घाटन सोहळा

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचे प्रतिपादन

आंबेडकरांना संस्कृत भाषा हवी होती

■ 60 एकरात साकारणार विद्यापीठ ■ 30,000 चौरस फुटात शैक्षणिक इमारत

महानगर प्रतिनिधी

विधी शिक्षण प्रणालीशिवाय हा स्तंभ मजबूत नाही

नागपूर. प्रशासकीय कामकाजात कोणत्या भाषेचा वापर करावा, याबाबत नेहमीच वाद होत राहिलेला आहे. तसेच न्यायालयात कोणत्या भाषेचा वापर करावा, यासंदर्भातही मतभेद आहेत. परंतु याबाबत कुणीही गंभीर नसल्याचे दिसून येते. या दिशेने संविधानाचे शिल्पकार डॉ. भीमराव आंबेडकर यांनी एक प्रस्ताव तयार केला होता. हा प्रस्ताव संसदेत सादर करण्यात आला अथवा नाही, याबाबत माहिती नाही. मात्र सर्व धर्मप्रमुखांसोबत चर्चा केल्यानंतर त्यांनी संस्कृतला अधिकृत भाषेच्या स्वरूपात प्रस्तावित केले होते, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी केले. बुधवारी वारंगा येथे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक भवनाचे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, न्यायाधीश भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, पालकमंत्री नितीन राऊत, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आदी उपस्थित होते.

न्या. बोबडे पुढे म्हणाले की, जर उत्तर भारतात तामिळचा वापर केल्यास तो स्वीकारण्यात येत नाही. याप्रमाणेच दक्षिणमध्ये हिंदी भाषा मान्य नाही. परंतु संस्कृतला उत्तर ते दक्षिणपर्यंत मान्यता मिळू शकते. लोकशाहीच्या 4 स्तंभात विधीचे वेगळेच महत्त्व आहे. परंतु सक्षम विधी शिक्षण प्रणालीशिवाय हा स्तंभ मजबूत होऊ शकत नाही. यामुळेच विधी विद्यापीठाचे स्वप्न साकार झाले आहे. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत तर्कांना अधिक महत्त्व देण्यात येते. एरिस्टोटल आणि पारसी प्रणालीत यास फार महत्त्व आहे. परंतु तज्ज्ञांसोबत झालेल्या चर्चेत प्राचीन भारतीय ग्रंथ न्यायशास्त्राला कोणत्याही प्रकारे कमी लेखण्यात आले नाही. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाची निर्मिती आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करण्यात आली आहे. ऑक्सफोर्ड, हॉवर्ड आणि कॅम्ब्रिज युनिव्हर्सिटीप्रमाणेच येथेही तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.



वकीलच नव्हे तर न्यायाधीशही होणार

न्या. बोबडे पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठात केवळ वकीलच नव्हे तर न्यायाधीशसुद्धा तयार होतील. त्यांना विशेष प्रशिक्षणही उपलब्ध केल्या जाईल. एनडीएप्रमाणे केवळ सैनिकच नव्हे तर न्यायिक अधिकारीही तयार होतील. या अनुषंगानेच काही अभ्यासक्रम तयार करण्यात आले आहे. लॉ युनिव्हर्सिटीसाठी न्यायाधीश भूषण गवई यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांची प्रशंसा त्यांनी यावेळी केली. तसेच राज्यात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी सर्वांनी यात योगदान दिले आहे. यासाठी भविष्यातील पिढी नेहमीच त्यांचे आभारी राहील. याप्रसंगी न्या. बोबडे यांनी न्यायमूर्ती भूषण गवई हे या विधी विद्यापीठाचे कुलपती असतील, असे जाहीर केले. विशेष म्हणजे 60 एकर जागेत विधी विद्यापीठ साकारण्यात येत आहे. पहिल्या चरणात 30,000 चौरस फुटात शैक्षणिक इमारतीचे बांधकाम करण्यात आले आहे. शिल्लक असलेले काम लवकरच पूर्ण होईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

राष्ट्रीय दृष्टिकोन विकासासाठी विधी...

वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक इमारतीचे उद्घाटन सरन्यायाधीश तथा या विद्यापीठाचे संस्थापक कुलपती शरद बोबडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी ते बोलत होते. दूरदृष्ट्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय भूपृष्ठ व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता, पालकमंत्री नितीन राऊत, ऊर्जा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्र, विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. विजेंद्रकुमार उपस्थित होते.

न्या. शरद बोबडे म्हणाले, या विद्यापीठातून विद्यार्थ्यांना थेट न्यायाधीश होण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. अभ्यासक्रमात त्यांना कोर्टरूमचा अनुभव, न्यायाधीशांसोबत वेळ घालविणे आणि इतरही प्रशिक्षण मिळणार आहे. त्यामुळे अभ्यासक्रम संपल्यावर ते न्यायाधीश होण्यास पात्र ठरतील.

गरिबांना न्याय मिळावा

संस्थेतून गोरगरिबांशी बांधीलकी जोपासणारे न्यायमूर्ती तयार व्हावेत. न्यायदानाच्या क्षेत्राला आदर आणि आधार देणारी विधी विद्यापीठ मोठी संस्था आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यातही न्यायदानाची परंपरा अत्यंत आदर्शवत होती. रामशास्त्री प्रभुनेसारख्या न्यायदात्यांनी ती पुढे चालवली. लोकशाहीचे छत समर्थपणे तोलून धरणारे वकील, विधिज्ञ या विद्यापीठात घडावेत, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

न्या. गवई नवे कुलपती

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आपल्या भाषणात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई विद्यापीठाचे नवे कुलपती असतील अशी घोषणा केली. सरन्यायाधीश २३ एप्रिलला सेवानिवृत्त होणार आहेत. न्या. बोबडे विद्यापीठाचे पहिले कुलपती होते. १३ एप्रिलला न्या. गवई यांची कुलपती म्हणून घोषणा केल्याचे ते म्हणाले.

राष्ट्रीय दृष्टिकोन विकासासाठी विधी विद्यापीठ महत्त्वपूर्ण

सरन्यायाधीश शरद बोबडे ; महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या शैक्षणिक इमारतीचे उद्घाटन

सकाळ वृत्तसेवा

नागपूर, ता. १४ : लोकशाहीच्या चौथा स्तंभ असलेल्या न्यायव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी चांगली विधी शिक्षण प्रणालीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाची निर्मिती करण्यात आली. त्यासाठी माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्यासह विविध राजकीय व्यक्तींचे योगदान आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ त्या दृष्टीने महत्त्वाचे आणि जागतिक दर्जाचे ठरणार आहे. राष्ट्रीय दृष्टिकोन आणि चारित्र्य विकसित करण्यासाठी हे विद्यापीठ निश्चितच



**उद्घाटन कार्यक्रमात बोलताना
सरन्यायाधीश शरद बोबडे.**

महत्त्वाचे योगदान देईल, असा आशावाद देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आज येथे व्यक्त केला.

पान २ वर »

राष्ट्रभाषा संस्कृत असावी हा बाबासाहेबांचा प्रस्ताव

देशात न्यायदान करताना नेमकी कोणती भाषा असावी याबाबत नेहमी चर्चा होत असते. मात्र, काही न्यायालयात इंग्रजी तर काही हिंदी आणि मराठीतून कामकाज करतात. मात्र, देशाची राष्ट्रभाषा कोणती असावी याबाबत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तेव्हा एक प्रस्ताव तयार केला होता. त्यात त्यांनी देशाची राष्ट्रभाषा संस्कृत असावी असे त्यात नमूद केले होते. मात्र, त्याचे काय झाले ते माहिती नाही. मात्र, हिंदीला दक्षिणेकडे विरोध आणि तमीळ आणि इतर भाषांना हिंदीबहुल राज्यात विरोध झाला असता, त्यामुळेच संस्कृत भाषा दोन्हीकडे मान्य असती त्यामुळे बाबासाहेबांनी या भाषेला राष्ट्रभाषा करण्यात यावी असा प्रस्ताव केला असावा असे न्या. बोबडे म्हणाले.

मराठी अनुवादित ग्रंथ विधी क्षेत्रासाठी उपयुक्त

पान २ वर »

विधि विद्यापीठ जागतिक दर्जा मिळविणार

◆ नागपूर, १४ एप्रिल

न्यायव्यवस्था हा लोकशाही व्यवस्थेचा अतिशय महत्वाचा स्तंभ आहे. तो मजबुत करण्यासाठी उत्तम दर्जाच्या विधि शिक्षणाची आवश्यकता असून येथील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ त्या दृष्टीने महत्वाचे आणि जागतिक दर्जाचे ठरणार आहे. राष्ट्रीय दृष्टिकोन आणि चारित्र्य विकसित करण्यासाठी हे विद्यापीठ निश्चितच महत्वाचे योगदान देईल, असा विश्वास सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आज येथे व्यक्त केला.

शहराजवळच्या वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या शैक्षणिक इमारतीचे उद्घाटन सरन्यायाधीश तथा या विद्यापीठाचे संस्थापक कुलपती शरद बोबडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी ते बोलत होते. दूरदृष्ट्य प्रणालीद्वारे झालेल्या या कार्यक्रमास

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना विश्वास

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, पालकमंत्री नितीन राऊत, तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुनील शुके, विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. विजेंद्रकुमार आदी उपस्थित होते.

भाषणाच्या प्रारंभी विधि विद्यापीठाच्या निर्मितीमागचा ओझरता प्रवास सरन्यायाधीशांनी मांडला. नागपूर शहराला असलेली उत्तम विधिज्ञांची गौरवशाली परंपरा पाहता इथे राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ

विधि विद्यापीठ इमारतीचे उद्घाटन



असावे, अशी येथील नागरिकांची इच्छा होती. आज त्यांची स्वप्नपूर्ती होत असल्याबद्दल

समाधान व्यक्त करून न्या. बोबडे म्हणाले, विद्यापीठाची शैक्षणिक इमारत हा आधुनिक वास्तुकलेचा सुंदर आविष्कार आहे. या इमारतीमधील वर्गखोल्यांचे बांधकाम हे जागतिक दर्जाचे आहे. अद्यावत तंत्रज्ञानाने सुसज्ज अशा या वर्गखोल्या आहेत. न्यायमूर्ती भूषण गवई या विधि विद्यापीठाचे कुलपती असतील, असे सरन्यायाधीशांनी यावेळी जाहीर केले. ते म्हणाले,

न्या. भूषण गवई कुलपती होणार

येथील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. या विद्यापीठातून राष्ट्रीय दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत होणार आहे. कारण देशभरातील प्राध्यापक आणि विद्यार्थी येथे अध्ययन- अध्यापन करणार आहेत. इथे प्रादेशिकता, संकुचितता यापेक्षा पुढे जाऊन राष्ट्रीय चारित्र्य असलेले विधिज्ञ घडतील. ऑक्सफर्ड- हॉवर्ड- केंम्ब्रीज या विद्यापीठांच्या तोडीचे विद्यापीठ ठरणार असल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी, लोकशाहीचे छत समर्थपणे तोलून धरणारे वकील, विधिज्ञ या विद्यापीठात घडावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

विधि क्षेत्रात गुणात्मक बदल व्हावा, त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विद्यापीठ उभारावे या उद्देशाने या विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आल्याचे सांगून नितीन गडकरी यांनी, मजबुत लोकशाहीचा एक स्तंभ न्यायव्यवस्थेचा असतो. तो उभारण्यासाठी विधि विद्यापीठाची महत्वाची भूमिका राहणार असल्याचे सांगितले.

प्रास्ताविक प्रा. आशीष सिंह यांनी केले तर आभार. प्रा. सी. रमेशकुमार यांनी मानले. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकर यांची यावेळी उपस्थिती होती. उद्घाटनानंतर मान्यवरांनी इमारतीची पाहणी केली. विधि विद्यापीठाच्या इमारतीची वैशिष्ट्ये दाखवणारी छोटी चित्रफित यावेळी दाखविण्यात आली.

◀(तथा वृत्तसेवा)

शहर में बढ़ रही हिंसक घटनाओं को रोकने आगे आया नागपुर विवि

■ पुलिस आयुक्तालय और महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ नागपुर के बीच सामंजस्य करार

निज प्रतिनिधि | नागपुर.

शहर में बढ़ रही हिंसक घटनाओं के पीछे की वजह के बारे में अब राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ मंडल संशोधन करेगा। साथ ही ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए उपाय योजना के बारे में भी रायशुमारी करेगा। मंगलवार को शहर पुलिस आयुक्तालय और महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ नागपुर के बीच इस संबंध में सामंजस्य करार हुआ है। इस करार पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार और कुलगुरु प्रा. डॉ. विजेंद्र कुमार ने हस्ताक्षर किया। शहर में हत्या, हत्या के प्रयास, लूटपाट व अन्य घटनाएं चिंता का विषय बनी रहती हैं। आपराधिक घटना के पीछे की वजह, अपराधियों की मानसिकता और अपराध के कारण को



लेकर मंथन किया जाएगा। इससे संबंधी संपूर्ण जानकारी शहर पुलिस विद्यापीठ के चयनित मंडल को उपलब्ध कराएगा। उसके बाद इस तरह के अपराध को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए क्या उपाय योजना करनी है। इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस कार्य के लिए किस तरह

के प्रशिक्षण या मार्गदर्शन की जरूरत है। यह भी निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद उपाय योजना को अमल में लाया जाएगा। इस तरह का सामंजस्य करार किया गया है। विधि विद्यापीठ के कुलगुरु प्रा. डॉ. विजेंद्रकुमार, ओएसडी (एकेडमी) प्रा. रमेशकुमार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुनील फुलारी, अतिरिक्त आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी मार्गदर्शक सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। विधि विद्यापीठ के सहायक प्रा. डॉ. रंगास्वामी स्टैलिन (सामाजिक शास्त्र, अपराध और न्याय वैज्ञानिक शास्त्र), सहायक प्रा. डॉ. हिमांशु पांडे (सबूत, कानून), सहायक प्रा. त्रिशा मित्तल (अपराध, कानून) और पुलिस विभाग की ओर से उपायुक्त विनीता साहू, लोहित मतानी, गजानन राजमाने संशोधन के कार्य करेंगे।



नागपुर सहित 147 परीक्षा केंद्रों पर 50% उपस्थिति में क्लैट का आयोजन पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम के लिए 10,434 ने कराया था पंजीयन

भास्कर प्रतिनिधि | नागपुर.

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शुक्रवार को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) नागपुर सहित देश के 147 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। नागपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने इस बार परीक्षा का आयोजन किया। परीक्षा संयोजक व यूनिवर्सिटी कुलगुरु डॉ. विजेंद्र कुमार के अनुसार सभी परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा का सफल आयोजन किया गया है। कहीं से कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। कोरोना संक्रमण के कारण इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर देश की सर्वोच्च

अदालत में याचिका दायर की गई थी। कुछ ही दिनों पूर्व सर्वोच्च अदालत ने याचिका खारिज करते हुए परीक्षा के आयोजन को हरी झंडी दी गई थी। बता दें कि शुक्रवार को दोपहर 2 से शाम 4 बजे के बीच पेन-पेपर मोड में यह परीक्षा हुई। परीक्षा के लिए अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 59,843 और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम प्रवेश के लिए 10,434 परीक्षार्थियों ने पंजीयन कराया था। कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था की गई थी। अंडरग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा में 150 प्रश्न 150 अंकों के लिए पूछे गए। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में 120 प्रश्न 120 अंकों के लिए पूछे गए।



MNLU organises virtual expert lecture on 'IP and Competition Law'

■ Staff Reporter

DEPARTMENT for Promotion of Industries and Internal Trade (DPIIT), IPR Chair at Maharashtra National Law University (MNLU) Nagpur launched the expert lecture series on the interface of Intellectual Property Rights with other laws.

The programme was organised under the leadership of Prof (Dr) Vijender Kumar, Vice-Chancellor, MNLU, Nagpur. The inaugural session was attended by Dr Ragini P Khubalkar, In-charge, DPIIT-IPR Chair and Assistant Professor of Law, MNLU, Nagpur. She delivered the welcome address and expressed the

need to understand the interface between IPR and Competition Law, role of TRIPS agreement, and CCI.

The sixth lecture of the expert lecture series was delivered by Isheta Batra, IP Counsel and Founder, TrailBlazer Advocates, Delhi on the topic 'Interface between IPR and Competition Law'. She provided an insight into the protection of IP and Competition Law and its violations.

She delivered her lecture by placing special emphasis on conflict and compatibility between Competition Law and IP and explained the need of healthy competition in the market.

Batra further elaborated on the

role of TRIPS agreement related to Competition Law and IP and its impact on the market as IP is a commercial asset which needs protection from the competitors. She explained the interface in details with support of examples. She explained the important aspects, background, aims and application of IP and Competition Laws.

The lecture was attended by law students and professionals. The lecture concluded with question and answer session. Shweta Kulkarni, Research Assistant of DPIIT-IPR Chair, MNLU, Nagpur took efforts for success of the programme, stated a press release.

नागपुर है विधिज्ञों की भूमि, उनके न्यायशास्त्र का लाभ उठाएं : बख्शी

भास्कर प्रतिनिधि/नागपुर. नागपुर ने देश को बेहतरीन विधिज्ञ दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रहे मोहम्मद हिदायतउल्लाह, न्या.ए.पी. सेन., न्या. विकास सिरपुरकर, पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति शरद बोबडे और वर्तमान न्यायमूर्ति भूषण गवई ने न्यायशास्त्र के विकास में अहम योगदान दिया है। उनके कार्यों का अकादमिक दृष्टि से लाभ उठाने के लिए महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एमएनएलयू) प्रयास करें। यह बात पद्मश्री पुरस्कृत विधि प्रोफेसर डॉ. उपेंद्र बख्शी ने संस्थान के एक वेबिनार में बतौर मुख्य वक्ता कही।

तो सफल होगा लोकतंत्र : एमएनएलयू के आईक्यूएसी विभाग और सेंटर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट लीगल स्टडीज के संयुक्त तत्वावधान में 'लेजिस्पूडेंस- ए थ्योरी ऑफ लेजिसलेशन इन इंडिया' विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रो. बख्शी ने विषय की बारीकियां समझाते हुए कहा कि भारत में न्यायशास्त्र को लेकर कुछ गलतफहमियां हैं। हमारे देश में लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक न्यायशास्त्र सफल नहीं होता। अच्छे अकादमिक अध्ययन तकनीकी रूप से जटिल इस विषय को उन्होंने विद्यार्थियों को सरल भाषा में समझाते हुए उनकी शंकाएं दूर की। प्रो. त्रिशा दुबे वेबिनार की मॉडरेटर थीं। प्रो. वी.पी. तिवारी के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में कुलगुरु, न्यायमूर्ति, वकील, विधि विद्यार्थी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।



Be a good researcher to be a good teacher: Prof Sinha

■ Staff Reporter

“YOU cannot be a good teacher, unless you are a good researcher. Hence, all the teachers must devote time to sit in the library, which is our temple and do quality research,” said Prof Dr Manoj Kumar Sinha, Director, Indian Law Institute, New Delhi. He was speaking during a national webinar organised by Maharashtra National Law University (MNLU)-Nagpur.

The webinar was on the topic ‘How to do Quality Research and Publish in Scopus/Index Journals’. The event was organised by Internal Quality Assurance Cell (IQAC) of MNLU-Nagpur under the able guidance of Prof Dr Vijender Kumar, Vice-Chancellor of the university.

Prof Sinha discussed the topic of the lecture in depth. He began the discus-



sion by stating that there were several journals of quality being published in India. However, he lamented, they have been closed in recent years because teachers have stopped researching and writing. He told the participants that there were many National and International journals being published and researchers must attempt to publish only in peer

reviewed journals listed in UGC Care list or otherwise. He emphasised that a good article must have abstract, introduction, and conclusion besides main body. He spoke on why, how and where to publish the articles.

Prof Trishla Dubey introduced the chief guest and conducted the programme. Dr V P Tiwari welcomed the guest and participants and also proposed a vote of thanks.

The programme was attended by more than 250 participants from all over the country. This was the second lecture in the series of programmes being organised by IQAC of MNLU-Nagpur. The IQAC committee consists of Prof Dr Vijender Kumar as Chairman, Dr V P Tiwari as Co-ordinator; and Professors Madhukar Sharma, Trishla Dubey, Nitu Kumari, and Jagdish Khobragade.

MNLU's on-line faculty devpt programme ends

■ Staff Reporter

THE DPIIT-IPR Chair and CIPR at Maharashtra National Law University (MNLU), Nagpur and the UGC-Human Resource Development Centre, DAVV, Indore, jointly organised online short-term faculty development programme on Intellectual Property Rights.

Prof Dr Vijender Kumar, Vice-Chancellor, MNLU, Nagpur, congratulated participants and association of the institutes for organising the programme with aim of contributing to 'Aatmanirbhar Bharat' mission. Prof Dr V C Vivekanandan, Vice-Chancellor, HNLU, Raipur, was the chief guest for valedictory function.

The one-week course was designed for training and orienting the faculties from various dis-

ciplines of higher education institutions from eight different States on emerging issues in Intellectual Property Rights regime. Dr Ragini P Khubalkar, Centre head and In-charge of DPIIT-IPR Chair, MNLU, Nagpur said that the aim of faculty development programme was to brief the teachers with new facets of Intellectual Property Rights. The co-organiser Prof Namrata Sharma, Director and Co-ordinator, HRDC, DAVV, Indore, also expressed her views. Shweta Kulkarni, Research Assistant with the DPIIT-IPR Chair, moderated the programme.

The programme consisted of 21 interactive sessions in the course of six days. More than 18 experts from respective fields from all over India addressed the participants on various areas of Intellectual Property.

'Law varsities should experiment, blend knowledge to create holistic professionals'

■ National webinar on 'Making of National Law Universities and Role of Teachers' through virtual platform held

■ Staff Reporter

"EVERY teacher is a sovereign. A teacher must have a clear intention, take responsibility, and lead accordingly. Vice-Chancellors also have to innovate, ideate, motivate faculties, and show them vision and path. The law universities should experiment, blend knowledge to create holistic professionals," said Prof Dr N L Mitra, formerly Director, National Law School University of India, Bangalore (the first National Law University) and founding Vice-Chancellor of NLU, Jodhpur.

Prof Dr N L Mitra was addressing a national webinar on 'Making of National Law Universities and Role of Teachers' through virtual platform. The event was organised by Internal Quality Assurance Cell (IQAC) of Maharashtra National Law University (MNLU), Nagpur.

The programme started with the welcome address of Prof Dr Vijender Kumar, Vice-Chancellor of MNLU, Nagpur. He recalled his long association with Prof Mitra and his commitment to the legal profession in general and legal education in particular. He informed the audience how Prof Mitra used his charismatic personality to eradicate financial crunches of National Law Universities (NLUs) and liaised with big corporate houses to create employment for the new law graduates of these NLUs.

Prof Mitra started his discussion by stating the difference between NLUs and the law colleges and law departments functioning under traditional universities. The faculties in NLUs are at liberty to design and redesign their syllabus, which could suit the industry, create

IQAC meet on September 30

THE IQAC of MNLU, Nagpur, chaired by Prof Dr Vijender Kumar is going to meet on September 30 to discuss the modalities of how to improve overall ranking of the University. Other members of the committee are Dr V P Tiwari, Co-ordinator; Professors Madhukar Sharma, Nitu Kumari, Trishla Dubey, Jagdish Khobragade, Dr Rengasamy Stalin, Sopan Shinde; alumnus Jhankruti Badani; Prof Dr Shyam Koreti, Head, Department of History, Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University; and Dr Aruna Nambala, Vice-President, All India Reporter Law Academy and Research Centre.

knowledge, make students employable. Whereas, traditional law colleges have to teach the course given to them by the universities, which may be old and outdated. There is scope for innovation and experimentation in NLUs. Prof Mitra explained how the course curriculum should be made, introduced to students so that they took interest in it. About framing question papers, he informed the participants that a teacher should not repeat the question in his life. He also discussed the issues in the present education system and the ways to overcome them.

Prof Trishla Dubey, moderator of the programme, introduced Prof Mitra. Dr V P Tiwari proposed a vote of thanks.

The programme was attended by around 100 participants from all over the country, which included many Vice-Chancellors including Prof S K Bhatnagar, Prof M K Shrivastava, Prof G S Bajpai; judges, advocates, academicians, students, and members from civil society.

MNLU students win 'Best Team Award' in mediation contest

■ Staff Reporter

STUDENTS of Maharashtra National Law University (MNLU), Nagpur brought laurels to the city by winning the 'Best Team Award' in Asia-Pacific Commercial Mediation Competition, recently.

The contest was conducted in collaboration with Australian Disputes Centre and the International Chamber of Commerce Australia. Debarpita Pande, Aditya Gatlewar and Sonal Okhade were the successful team members of MNLU who performed well in the competition.

The team bagged 'Best Team Award' in



Debarpita
Pande



Aditya
Gatlewar



Sonal
Okhade

Mediation Relationship Building and also declared the winner in Impromptu Speech Competition.

Prof Dr Vijender Kumar, Vice-Chancellor, MNLU congratulated the team for their success.

Published On : Tue, Sep 21st, 2021

Latest News / Nagpur Happening News | Nagpur | By Nagpur Today Nagpur News

MNLU Nagpur should explore the legal jurisprudence evolved by the judges and jurists from nagpur – Upendra Baxi



NAGPUR: Padma Shri Awardee and eminent law Professor – Dr. Upendra Baxi virtually addressed a national webinar on “Legisprudence: A Theory of Legislation in India” at Maharashtra National Law University, Nagpur. The event was organised by Internal Quality Assurance Cell (IQAC) in association with Centre for Post-Graduate Legal Studies (CPGLS).

Prof. (Dr.) Upendra Baxi fondly recalled his memories of Nagpur and the great hospitality offered to him earlier on his visits to Nagpur including Saoji delicacies. He underlined the contribution made in the Indian legal jurisprudence by people like Professor Raghavan, Prof. Laxmi Nath, and Judges like Justice Hidayatullah, Justice AP Sen, Justice VS Sirpurkar, former Chief Justice of India Justice SA Bobde and Justice BR Gavai, who is future Chief Justice of India. Prof. Baxi appealed to the Vice Chancellor of MNLU, Nagpur through Dr VP Tiwari, the Coordinator of the webinar to explore the legal jurisprudence evolved by these great judges and other legal luminaries from Nagpur and also from Maharashtra, which would be great service to the society.

Prof. Baxi discussed the topic of lecture in great depth wherein he began the discussion by outlining the three main prudence: jurisprudence, legisprudence and demoprudence. He stated that jurisprudence is study of living law and it is greatly misunderstood in India. He gave a detailed presentation on legisprudence wherein he elucidated the theory of legislation, nature and scope of delegated legislation, identifying purpose and intent of law, functions of legislation, law and legitimate social expectations, right to repeal, right to protection and responsible sovereignty.

He discussed the democratic dignity of legislature and the practical aspects of separation of powers in India. He emphasised the need to study administrative law, statutory law and legislative drafting as one subject in a holistic manner. In conclusion, he stated that "You cannot take democracy seriously unless we take legisprudence seriously".

The moderator of the programme Prof. Trishla Dubey introduced the Chief Speaker and recalled that Prof. Baxi is a man of principle and standing and has immensely contributed to almost all the fields of law including social action litigation which brought respite to the inmates of Agra Protective Homes whose life was very deplorable before his interventions.

The programme was attended by around 500 participants from all over the country, which included many Vice Chancellors, judges, advocates, academicians, bureaucrats, students and members from civil society. This was inaugural programme of IQAC of the University which was recently constituted by the Hon'ble Vice Chancellor Prof. (Dr.) Vijender Kumar to ensure that the University becomes centre of excellence and attains very high ranking in NIRF, an agency constituted to rank Indian academic institutions.

The committee members include Dr VP Tiwari, Coordinator, Professors Madhukar Sharma, Trishla Dubey, Nitu Kumar and Jagdish Khobragade. The guests were welcomed and thanked by Dr VP Tiwari on behalf of Hon'ble Vice Chancellor, who could not attend the function due to some sudden official work.

<https://www.nagpurtoday.in/mnlu-nagpur-should-explore-the-legal-jurisprudence-evolved-by-the-judges-and-jurists-from-nagpur-upendra-baxi/09211657>

उत्तम संशोधकच शिक्षक होऊ शकतो

प्रा. एम. के. सिन्हा
यांचे मत

राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा
आभासी उपक्रम

♦ नागपूर, २२ सप्टेंबर

संशोधनवृत्ती ही सर्वासाठी आवश्यक आहे, पण त्यातही शिक्षकी पेशातील व्यक्तींनी संशोधन वृत्तीकडे अधिक लक्ष द्यावे. कारण उत्तम संशोधकच चांगला शिक्षक होऊ शकतो, असे मत इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूट नवी दिल्लीचे संचालक प्रा. एम. के. सिन्हा यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी नागपूरतर्फे आयोजित राष्ट्रीय वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले. त्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून प्रा.



सिन्हा बोलत होते. याप्रसंगी विधी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजेंद्रकुमार उपस्थित होते.

याप्रसंगी बोलताना प्रा. सिन्हा म्हणाले, देशभरात दर्जेदार संशोधन प्रकाशित करणारी अनेक जर्नल्स कार्यरत आहेत. पण मागील अनेक वर्षांपासून शिक्षकांनी संशोधन पूर्णतः बंद केल्याचे जाणवत आहे. पण उत्तम संशोधकाशिवाय चांगला शिक्षण होणे शक्य नाही. यासाठी सर्व शिक्षकांनी दैनंदिन जीवनातील अधिक काळ ग्रंथालयात देण्याची गरज आहे, तेच संशोधनाचे मंदिर आहे, असेही सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.

बहुतांश शिक्षक केवळ आपले नाव यावे यासाठी शोधनिबंधाचा आढावा घेण्यात व्यस्त आहेत. उत्तम शोधनिबंधाला प्रस्तावना, समारोप आणि त्याचा मथितार्थ असणे आवश्यक असल्याचेही प्रा. सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.

प्रा. सिन्हा यांनी आंतरराष्ट्रीय कायदे, शरणार्थी कायदा, मानवाधिकार, घटनात्मक कायदे आदी विषयांवर संशोधन केले आहे. देशातील व विदेशातील अनेक विद्यापीठांशी त्यांचा थेट संबंध आहे. संचालन प्रा. त्रिशा दुबे यांनी केले. आभारप्रदर्शन डॉ. व्ही. पी. तिवारी यांनी केले. यावेळी समन्वयक मधुकर शर्मा, नीतू कुमारी आणि जगदीश खोब्रागडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.

◀(तभा वृत्तसेवा)

MNLU Nagpur signs pact with ICSI

Nagpur: Maharashtra National Law University (MNLU) Nagpur signed a MoU with Institute of Company Secretaries of India (ICSI) on Sunday.

The pact was signed at the annual regional conference of ICSI by MNLU vice-chancellor Prof Vijender Kumar and ICSI president Nagendra Rao in the presence of WIRC chairman Pawan Chandak, ICSI Nagpur chapter



chairperson Khushboo Pasari, MNLU Nagpur OSD (academics) Chamarti Ramesh Kumar and registrar Ashish Dixit.

The MoU was signed to promote excellence inter-alia in common areas of interest, imparting knowledge and skills required to operate in area of academics, research and training. The MoU also promotes to jointly organize workshops, seminars for continuing education and capacity building training programmes for practicing professionals, corporate executives, faculty members and research scholars. TNN

MNLU conducts virtual mental health camp

Nagpur: To sensitize and raise awareness about suicide prevention, Maharashtra National Law University (MNLU), conducted a two-day virtual mental health camp on the occasion of World Suicide Prevention Day, under the guidance of vice-chancellor Prof Vijender Kumar.

The camp was held under the guidance of Kartika Jamdar, Dipti Christian and Rowena Ajay Philips to help address the various challenges. A number of students participated in one-to-one counselling session on the first day.

On day two, an international webinar titled 'Creating Hope through Action' was conducted. The webinar was hosted by university's in-house consulting psychologist Rowena Phillips and Ragini Khubalkar, faculty advisor of gender sensitisation committee of MNLU.

Chief guest for the programme was Paralympic Games performance coach and former IT professional Keith Antoine. TNN

MNLU Nagpur team wins intl mediation contest

2021/10/5 11

The Maharashtra National Law University (MNLU) Nagpur team received best team award in **mediation relationship building** in the **Asia-Pacific**



Debarpita Pande (from left), Aditya Gatlewar and Sonal Okhade of MNLU Nagpur

Commercial Mediation Competition conducted by **Australian Disputes Centre** and International Chamber of Commerce Australia. The team, comprising **Debarpita Pande**, Aditya Gatlewar and **Sonal Okhade**, was also declared winner in impromptu speech competition. MNLU vice-chancellor **Prof Vijender Kumar** congratulated the team of Debarpita, Aditya and Sonal on their success in the international event. **Debarpita** and **Aditya** have just completed their undergraduate degree from **MNLU Nagpur** and **Sonal** is currently in the final year of undergraduate programme.

निधि के कारण विधि विद्यापीठ का निर्माणकार्य नहीं रुकेगा : सामंत

■ वित्त मंत्री से की जाएगी चर्चा

भस्कर संवाददाता | नागपुर। राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने स्पष्ट किया कि निधि की कमी के कारण महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ की इमारत का निर्माणकार्य नहीं रुकेगा। पहले चरण में निधि की कमी के कारण निर्माणकार्य अधूरा रहा। इसमें 13 इमारतें शामिल हैं। शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू होगा। 95 करोड़ निधि की जरूरत है। इसे उपलब्ध कराने के लिए उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार से चर्चा की जाएगी। मंत्री सामंत ने विधि विद्यापीठ परिसर की नई इमारत के निर्माणकार्य का निरीक्षण किया।

इनकी रही उपस्थिति : मंत्री सावंत वरुणा स्थित महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ की बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान विद्यापीठ



के कुलगुरु डॉ. विजेंद्र कुमार, लोक कर्म विभाग के कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे, कुलसचिव आशीष दीक्षित, सहायक कुलसचिव रंगास्वामी स्टैलीन, विशेष कार्य अधिकारी रमेश कुमार, राज शिष्टाचार अधिकारी रमेश मानापुरे, प्रो. हिमांशु पांडे, प्रो. सोपान शिंदे, वास्तु विशेषज्ञ सलाहकार पी. एस. आहूजा उपस्थित थे। कुलगुरु ने अधूरी इमारत के लिए जरूरी निधि शीघ्र देने की मांग की।



MNLU to get necessary funds to develop basic facilities, assures Samant

■ State Finance Minister Ajit Pawar to convene meeting

■ Principal Correspondent

MAKING it clear that the first phase construction of Maharashtra National Law University (MNLU) is pending, Higher and Technical Education Minister Uday Samant said, "There are 13 buildings whose work is incomplete for which the fund of Rs 95 crore is needed. To get the funds sanctioned we are arranging the meeting of university administration with Finance Minister Ajit Pawar."

Samant had been to Warange, from where the MNLU is functioning. Vice-Chancellor Dr Vijender Kumar, Executive Engineer Janardhan



Minister Uday Samant interacting with MNLU Vice-Chancellor Dr Vijender Kumar. Ramesh Kumar, Paramjit Singh Ahuja and others look on.

Bhanus, Public Works Department, Registrar Ashish Dixit, Assistant Registrar Rangaswamy Stalin, Officer on Special Duty Ramesh Kumar, Protocol Officer Ramesh Manapure, Prof Himanshu Pandey, Prof Sopan Shinde, Architect Advisor Paramjeet Singh Ahuja were present.

Academic building, administrative building, students' two hostels, dining room, staff residence, etc are the ones whose work is still incomplete.

If the funds are available with the State Government, then it should not be kept pending and be released immediately, instructed Samant to officers.

Vice-Chancellor Dr Vijender Kumar has put his demand of sanctioning the required fund as early as possible.

MNLU holds workshop

THE DPIIT-IPR Chair and CIPR at Maharashtra National Law University (MNLU), Nagpur conducted a workshop on 'Hands On Training: Research Methods in Intellectual Property Rights', in association with Cochin University of Science and Technology (CUSAT).

The programme was organised under the leadership of Prof Dr Vijender Kumar, Vice Chancellor, MNLU and Dr Ragini P Khubalkar, In-charge, DPIIT-IPR Chair and Assistant Professor of Law, MNLU. Dr Ragini P Khubalkar delivered the welcome address. The training was conducted by Dr Anson CJ, Assistant Professor, Inter University Centre for IPR Studies, Cochin University of Science and Technology.

UGC's Expert Committee inspects MNLU-Nagpur

■ The Expert Committee was headed by Prof Dr Balraj Chauhan

■ Staff Reporter

A FOUR-MEMBER Expert Committee constituted by the Chairman of University Grants Commission (UGC) visited Maharashtra National Law University (MNLU), Nagpur on October 28 and October 29.

The Expert Committee was headed by Prof Dr Balraj Chauhan, former Vice-Chancellor of NLIU, Bhopal, RMLNLU, Allahabad and DNLU, Jabalpur.

The committee comprised Prof Dr Dharmendra Kumar Mishra, Faculty of Law, Banaras Hindu University; Prof Dr Prakash Singh, Department of Political Science, Delhi University, as Members; and Dr Avichal Kapur, Joint Secretary, UGC, as Co-ordinating Officer.

The committee interacted with the officers of MNLU Nagpur, including Prof Dr Vijender Kumar, Vice-Chancellor; Dr Ashish J Dixit, Registrar; Deputy Registrar and Assistant Registrars; and Prof Dr Himanshu Pandey, Co-ordinator for UGC 12B Expert Committee visit. The committee also interacted with the members of governing bodies, faculty, Heads of Centres, non-teaching staff, University doctors and counselor, research scholars, students and alumni.

The Expert Committee inspected academic building, Library, Examination Section, Accounts Section, Legal Aid Clinic, administrative building and hostels.

The UGC provides financial assistance to eligible universities and colleges included under Section 12 (B) of UGC Act, 1956 as per approved pattern of assistance under various schemes, stated a press release.

विधी विद्यापीठ बांधकामासाठी अर्थमंत्र्यांकडे बैठक होणार उदय सामंत यांनी घेतला आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि
विद्यापीठाच्या इमारत बांधकामातील



पहिल्या
टप्प्यात
असलेले
बांधकाम
निधीअभावी
अपूर्ण राहिले

आहे. यामध्ये १३ इमारतींचा समावेश आहे. ते बांधकाम लवकर पूर्ण करून प्रत्यक्ष वर्ग सुरू व्हावेत. त्यासाठी ९५ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. हा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत लवकरच विद्यापीठ प्रशासनाची मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ येथे आयोजित आढावा बैठकीत सामंत बोलत होते. विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजेंदर

कुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे, कुलसचिव आशिष दीक्षित, सहाय्यक कुलसचिव रंगास्वामी स्टॅलिन, विशेष कार्य अधिकारी रमेश कुमार, राजशिष्टाचार अधिकारी रमेश मानापुणे, प्रो. हिमांशू पांडे, प्रो. सोपान शिंदे, वास्तुशास्त्रज्ञ सल्लागार पी. एस. आहुजा उपस्थित होते.

पहिल्या टप्प्यातील बांधकाम निधीअभावी थांबले असून, ते लवकर पूर्णत्वास नेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील. विधि विद्यापीठ परिसराबाबत समाधान व्यक्त करून विद्यापीठाचे बांधकाम लवकर पूर्ण झाल्यास त्याचा मोठा लाभ महाराष्ट्राच्या विधि क्षेत्राला मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.

या अपूर्ण इमारत बांधकामामध्ये शैक्षणिक इमारत, प्रशासकीय इमारत, विद्यार्थ्यांचे दोन वसतिगृह, भोजन कक्ष, कर्मचारी निवासस्थानांचा समावेश आहे.

एम्स-महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठात सामंजस्य करार

न्यायवैद्यकशास्त्रातील संशोधन, अभ्यासक्रमासाठी मदत



सामंजस्य कराराप्रसंगी उपस्थित डॉ. विभा दत्ता, डॉ. विजेंद्र कुमार, डॉ. मनीष श्रीगिरीवार.

लोकसत्ता खास प्रतिनिधी

नागपूर : न्यायवैद्यकशास्त्राशी संबंधित संशोधन, नवीन पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासह विविध विषयातील तज्ज्ञांना या विषयातील प्रशिक्षणासाठी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था आणि महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठामध्ये गुरुवारी सकाळी १०.३० वाजता सामंजस्य करार झाला.

करारावर एम्सच्या संचालिका मेजर जनरल (निवृत्त) डॉ. विभा दत्ता, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजेंद्र कुमार यांनी स्वाक्षरी केली. याप्रसंगी एम्सच्या न्यायवैद्यकशास्त्र विभागाचे प्रमुख व वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मनीष श्रीगिरीवार, अधिष्ठाता डॉ. मृणाल फाटक, राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाचे प्रा. डॉ. रेंगासामी स्टॅलिन, प्रा. त्रिशा मित्तल यांच्यासह दोन्ही

संस्थेचे अधिकारी उपस्थित होते. या करारामुळे न्यायवैद्यकशास्त्राशी संबंधित विषयावरील संशोधन सहकार्य, नवीन पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, वार्षिक आंतरराष्ट्रीय संशोधन परिषदेसाठी दोन्ही संस्था मदत करतील. सोबत न्यायाधीश, सरकारी वकील, पोलीस अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी आणि इतर गुन्हे तपास यंत्रणा यांच्यासाठीचे प्रशिक्षण कार्यक्रमही एकत्र घेतले जातील. या करारामुळे न्यायवैद्यकशास्त्र विभाग (एम्स), नागपूर व महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ या दोन्ही संस्था आधुनिक पद्धतीने न्यायवैद्यकीय पुरावे गोळा करणे, गुन्हांची उकल करण्याच्या दृष्टीने या पुराव्यांची योग्य मांडणी करणे, तसेच वैद्यकीय व्यवसाया संदर्भातील नियम व कायदे यांची माहिती करून देणे यासाठी कटिबद्ध होतील, अशी माहिती डॉ. श्रीगिरीवार यांनी दिली.



अर्थमंत्र्यांकडे लवकरच बैठक

उदय सामंत : आवश्यक निधी तत्काळ मिळवून देणार

सकाळ वृत्तसेवा

नागपूर, ता. २ : महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठाच्या इमारत बांधकामातील पहिल्या टप्प्यात असलेले बांधकाम निधीअभावी अपूर्ण राहिले आहे. यामध्ये १३ इमारतींचा समावेश आहे. ते बांधकाम लवकर पूर्ण करून प्रत्यक्ष वर्ग सुरू व्हावेत. त्यासाठी ९५ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. हा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत लवकरच विद्यापीठ प्रशासनाची मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय

विधि विद्यापीठ येथे आयोजित आढावा बैठक घेतली. यावेळी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजेंदर कुमार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जनार्दन भानुसे, कुलसचिव आशिष दीक्षित, सहायक कुलसचिव रंगास्वामी स्टॅलिन, विशेष कार्य अधिकारी रमेश कुमार, राजशिष्टाचार अधिकारी रमेश मानापुरे, प्रो. हिमांशू पांडे, प्रो. सोपान शिंदे, वास्तुशास्त्रज्ञ सल्लागार पी. एस. आहुजा उपस्थित होते.

पहिल्या टप्प्यातील बांधकाम निधीअभावी थांबले असून, ते लवकर पूर्णत्वास नेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील. विधी विद्यापीठ परिसराबाबत समाधान व्यक्त करून

विद्यापीठाचे बांधकाम लवकर पूर्ण झाल्यास त्याचा मोठा लाभ महाराष्ट्राच्या विधि क्षेत्राला मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.

या अपूर्ण इमारत बांधकामामध्ये शैक्षणिक इमारत, प्रशासकीय इमारत, विद्यार्थ्यांचे दोन वसतिगृह, भोजन कक्ष, कर्मचारी निवासस्थानांचा समावेश आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी निधी गरज आहे. त्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. तसेच राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर हा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे प्रलंबित न ठेवता तो विनाविलंब उपलब्ध करून देण्याचे आदेश सामंत यांनी संबंधितांना दिले.

Nagpur, Nagpur-Today
03/10/2021 Page No. 2

विधि विद्यापीठ बांधकामाचा निधी मिळविणार

उच्च व तंत्रशिक्षण
मंत्र्यांनी घेतला आढावा
विद्यापीठ प्रशासनाची
मुंबईत बैठक

◆ नागपूर, २ ऑक्टोबर
महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि
विद्यापीठाच्या इमारत बांधकामातील
पहिल्या टप्प्यात असलेले बांधकाम
निधीअभावी अपूर्ण राहिले आहे.
यामध्ये १३ इमारतींचा समावेश आहे.
ते बांधकाम लवकर पूर्ण करून
प्रत्यक्ष वर्ग सुरू व्हावेत. त्यासाठी
९५ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज
आहे. हा निधी उपलब्ध करून
देण्यासाठी अर्थमंत्री अजित पवार
यांच्यासोबत लवकरच विद्यापीठ
प्रशासनाची मुंबईत बैठक आयोजित
करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र
शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी
सांगितले.

वारंगा येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय



विधि विद्यापीठ येथे आयोजित
आढावा बैठकीत सामंत बोलत होते.

विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.
विजेंदर कुमार, सार्वजनिक बांधकाम
विभागाचे कार्यकारी अभियंता
जनार्दन भानुसे, कुलसचिव आशीष
दीक्षित, सहायक कुलसचिव
रंगास्वामी स्टॅलीन, विशेष कार्य
अधिकारी रमेश कुमार, राजशिक्षाचार
अधिकारी रमेश मानापुरे, प्रो. हिमांशु
पांडे, प्रो. सोपान शिंदे, वास्तुशास्त्रज्ञ
सल्लागार पी. एस. आहुजा उपस्थित

होते.

पहिल्या टप्प्यातील बांधकाम
निधीअभावी थांबले असून, ते लवकर
पूर्णत्वास नेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न
करण्यात येतील. विधि विद्यापीठ
परिसराबाबत समाधान व्यक्त करून
विद्यापीठाचे बांधकाम लवकर पूर्ण
झाल्यास त्याचा मोठा लाभ
महाराष्ट्राच्या विधि क्षेत्राला मिळणार
असल्याचे ते म्हणाले.

या अपूर्ण इमारत बांधकामामध्ये
शैक्षणिक इमारत, प्रशासकीय इमारत,

विद्यार्थ्यांचे दोन वसतिगृह, भोजन
कक्ष, कर्मचारी निवासस्थानांचा
समावेश आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी
निधी गरज आहे. त्यासाठी शासन
स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येत
असल्याचे ते म्हणाले. राज्य शासनाने
निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतर हा
निधी जिल्हा प्रशासनाकडे प्रलंबित न
ठेवता तो विनाविलंब उपलब्ध करून
देण्याचे आदेश सामंत यांनी
संबंधितांना दिले. सामंत यांनी विधि
विद्यापीठ परिसरातील नूतन इमारत
बांधकामाच्या प्रगतीबाबत पाहणी
केली तसेच विकासकामांबाबत
लागणारा निधी उपलब्ध करून
देण्यात येणार असल्याचे यावेळी ते
म्हणाले. कुलगुरू डॉ. विजेंदर कुमार
यांनी विधि विद्यापीठ इमारतीचे झालेले
बांधकाम आणि अपूर्ण राहिलेल्या
इमारतींना लागणारा निधी लवकरच
लवकर मिळण्याची मागणी सामंत
यांच्याकडे केली.

◀(तथा वृत्तसेवा)

AIIMS signs MoU with Maharashtra National Law University, Nagpur today for the purpose of Research Collaboration

written by [TLN Team](#) October 21, 2021



The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Nagpur has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Maharashtra National Law University, Nagpur on Thursday, October 21, 2021 for the purpose of Research Collaboration that will encompass between the two institutions through the Students and Faculty Members of MNLU, Nagpur and of AIIMS, Nagpur.

The research collaboration encompasses Post-Graduate Diploma Programs, International Conference, Training programs for the Judiciary/Police Officers/Public Prosecutors/Medical Officers, and, other research activities like research projects.

These activities will be joint venture of AIIMS, Nagpur & MNLU. It intends to benefit academicians and professionals by extending expertise of AIIMS Nagpur & MNLU, Nagpur. It will improve the quality of criminal investigations and hence increase the criminal conviction rate.

The MoU was signed by Maj Gen (Dr). Vibha Dutta, SN, Director & CEO of AIIMS Nagpur and Prof. (Dr.) Vijender Kumar, Vice-Chancellor of MNLU, Nagpur in the presence of the core team members Dr Manish Shrigiriwar, Professor, Department of Forensic Medicine & Toxicology, AIIMS Nagpur and Dr. Rengasamy Stalin, Prof. Sopan Shinde, Assistant Professors MNLU were present at the occasion.

First phase of MNLU campus to be ready soon: Edu min

Manshika Vaikkath | TNN

Nagpur: The construction of the first phase of the Maharashtra National Law University (MNLU), which includes 13 buildings, has remained incomplete due to lack of funds. The completion of the construction in order to start classes soon requires Rs 95 crore.

A meeting of the university administration will be held in Mumbai soon with state finance minister Ajit Pawar to make the funds available, said higher and technical education minister Uday Samant.

Samant was speaking at the review meeting held at MNLU at Waranga.

MNLU vice-chancellor Vijender Kumar, public works department executive engineer Janardan Bhanuse, registrar Ashish Dixit, assistant registrar Rangaswamy Stalin, special operations officer Ramesh Kumar, Ramesh Manapure, professor Himanshu Pandey, professor Sopan Shinde, PS Ahuja were present.

Samant added, "The construction of the first phase was stalled due to lack of funds and every effort will be made to complete it as soon as possible." Expressing satisfaction regarding the campus, he said that if the construction of the university is completed soon, it will be of

great benefit to the law sector in Maharashtra.

The unfinished work includes an educational building, an administrative building, two student dormitories, a dining room and staff quarters. He informed that funding to accomplish this is being followed up at the government level. "Funds released by the state government were made available to the district administration without any delay," he said.

Samant inspected the progress of construction of the new building on the MNLU premises. Kumar stressed on the need for funds required for the unfinished buildings.

Maha National Law Univ holds webinar on research



The internal quality assurance cell (IQAC) of **Maharashtra National Law University (MNLU)**, Nagpur, organized a webinar on

'How to do quality research and publish in Scopus/index journals'. Director of **Indian Law Institute**, New Delhi, **Prof Manoj Kumar Sinha** was the main speaker. **Prof Sinha** said, "You cannot be a good teacher unless you are a good researcher. All teachers must devote time to sit in the library, which is our temple and do **quality research**. Researchers must attempt to publish their paper only in peer reviewed journals which are listed in UGC care list." He said that a **good article** must have **abstract**, introduction and conclusion besides the main body. The programme, organized under able guidance of **MNLU** vice-chancellor **Prof Vijender Kumar**, was attended by more than **250 participants** from all over the country. It was compered by Prof Trishla Dubey while VP Tiwari proposed vote of thanks.

AIIMS signs MoU with Mah National Law University

The All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Nagpur, signed an MoU with Maharashtra National Law University on



Thursday for the purpose of research collaboration. The collaboration encompasses **PG diploma programmes**, international conference, training programmes for the judiciary, police officers, public prosecutors, medical officers and other research activities. These activities will be joint venture of **AIIMS** and **MNLU**. It will improve the quality of criminal investigations and hence increase the criminal conviction rate. The MoU was signed by **Maj Gen (Dr) Vibha Dutta**, director of AIIMS and **Prof Vijender Kumar**, vice-chancellor of MNLU, in the presence of the core team members. **Dr Manish Shrigiriwar** of AIIMS and **Dr Rengasamy Stalin** and **Prof Sopan Shinde** of MNLU were also present.

NLU study finds direct link between city's temperature and murders

■ By Dheeraj Fartode

A STUDY conducted by National Law University (NLU), Nagpur has shown declining trend in murder cases in city in last two decades. Interestingly, the study has found direct relation between murder cases and city weather. In cases reported from 2001 to 2020, the months of May, June and October have seen highest murders while the months of December and January have reported low-est murders.

The NLU conducted the micro analysis of body offences in the Second Capital on the request of Nagpur City Police. The study revealed that in last 20 years, murder cases have shown declining trend

SPECIAL REPORT

in the city. As compared to 980 murders reported from 2001 to 2010, the city registered 901 cases from 2011 to 2020. It may be mentioned that Nagpur has witnessed 79 murders till October 21 this year. Based on the data and micro analysis, the study has also

16 murders due to love affairs, illicit relationship till Oct 2021

A TOTAL of 79 murders took place between January and October 21, 2021. Of them, love affairs and illicit relationship were reasons behind 16 murder cases. Disputes that triggered sudden rage was the reason behind 21 murders while old-rivalry led to 16 murders. Ten were killed in drunken brawls. There were 15 murders over monetary disputes. "Most of these cases were not preventable," Commissioner of Police Amitesh Kumar said.

projected that the year 2023 would witness around 75 murders in city.

Commissioner of Police (CP) Amitesh Kumar informed 'The Hitavada' that the analysis was necessary to ascertain the reasons behind body offences. "The analysis would help the police
(Contd on page 4)

NLU study finds direct link between city's temperature and murders

in taking measures accordingly to reduce body offences in the city," he said.

Detailed analysis of murder cases shows that highest number of murders were reported in May, June and October months in the last two decades while December and January months reported lowest number of murder cases.

From 2001 to 2010, cumulative 92, 112 and 99 murders were reported in May, June and October, respectively. The trend continued in the next decade (2011 to 2020) with 95 murders in May, 93 in June and 81 murders in October months.

In January and December cumulative 63 and 68 murders were reported from 2001 to 2010 and the same reflected in next decade (2011 to 2020) as 54 murders reported in January and 64 in December months.

As per the study, the increase in murder cases was directly proportional to the temperature as the city witnesses high temperature in these months. December and January reported the lowest murders due to winter.

However, a section of senior police officers does not agree

with the projected number of murders. Ex-CP of Nagpur Prabir Chakraborty said that there was no direct relation between crime and time. "If heat is taken as the reason behind body offences, then Jaisalmer, which is famous for high temperatures, should have the highest body offences in India," he said.

"Along with the murder cases, the study needs to focus on the assault and attempt to murder cases reported in the past two decades, Chakraborty added.

Ex-Director General of Police and former Nagpur CP Pravin Dixit said that such study was conducted during the time of Britishers. "Impact of environment on human behaviour can be ascertained by studying patterns for a minimum 100 years. The City Police should study crime records of the past several decades before reaching to any conclusion," he said.

"As liquor consumption is one of the reasons behind murders, police should study whether people consume liquor more in hot weather or winter," Dixit added.

MNLU, MSBB hold International webinar on Access and Benefit Sharing

■ Webinar aims at developing jurisprudence of ABS mechanism by examining existing knowledge on biodiversity and its conservation

■ Staff Reporter

MAHARASHTRA National Law University (MNLU), Nagpur in collaboration with Maharashtra State Biodiversity Board (MSBB), Nagpur inaugurated a two-day International webinar on 'Access and Benefit Sharing: Sustaining Indian Biodiversity' on Friday.

The inaugural session was followed by five parallel technical sessions wherein academicians and, practicing professionals pre-

sented their research papers on five identified themes. The International webinar aimed at discussing Biodiversity and Human Rights, Stakeholder Participation and Role and Contribution of CSR, Access and Benefit Sharing (ABS) Legislation in India, ABS and Intellectual Property, and ABS Litigation in India.

The webinar aimed at developing jurisprudence of ABS mechanism by critically examining existing knowledge on biodiversity and its conservation; to identify gaps in legal and institutional framework on ABS mechanism in India; and to discuss issues like bio-piracy, conflict with IPR, role and responsibilities of Government institutions such as State Biodiversity Boards and National Biodiversity Authority, Indian cor-

porate houses, and research institutions, etc. Prof Dr Vijender Kumar, Vice-Chancellor of MNLU Nagpur, elucidated on biodiversity and ABS related issues in his welcome address. Praveen Shrivastava, Member Secretary, MSBB, Nagpur gave an overview of developments in the State concerning biodiversity conservation, sustainable use, and ABS in his welcome address.

Justice Virendra Dutta Gyani, former Acting Chief Justice, Guwahati High Court, and the chief guest of the inaugural ceremony, emphasised on the necessity of implementing the Biodiversity Act, 2002 in its letter and spirit. The guest of eminence Andrew Mitchell, Senior Forestry Specialist, World Bank, traced the history of forest ownership and highlighted the importance of local communities in

forest management wherein ABS aided conservation and sustainable use of biodiversity in many countries.

Guest of honour BV Umadevi, Additional Secretary, Ministry of Environment, Forest, and Climate Change, reviewed the current status of Indian ABS framework and the readiness of implementing institutions from national to local levels. Another guest of honour Justin Mohan, Member Secretary of National Biodiversity Authority, narrated his grassroots level experiences of implementing ABS in India.

Trishla Dubey, Convenor of the programme, presented a concept note and proposed a vote of thanks. The webinar received overwhelming response from academicians, research scholars, professionals, and practitioners from India and abroad.

**FIRST
COLUMN****Year 2022 to
witness two
CLAT exams****■ MNLU V-C**

Dr Vijendra Kumar
becomes
Vice-President of
Consortium of
National Law
Universities

■ Principal Correspondent

THE year 2022 will witness
two
Common
Law
Admission
Test (CLAT)
in one sin-
gle year.



Dr Vijender
Kumar

The Annual
Executive
Committee
and the

General Body Meetings of
the Consortium of
National Law Universities
were held at NALSAR
University of Law,
Hyderabad under the
Chairmanship of Prof.
Faizan Mustafa on
Monday. In the meeting
the decision regarding
holding CLAT was taken.

According to the deci-
sion, Common Law
Admission Test (CLAT) -22
for the admissions to vari-
ous national law univesi-
ties for the year 2022 will
be held on May 8, 2022.

The Consortium has
also resolved that CLAT-
2023 will be held on
December 18, 2022.
Hence, in 2022 two CLAT
examinations will be held
in one year.

The Consortium has
also elected a new
Executive Committee with
Prof. Poonam Saxena,
Vice-Chancellor, National
Law University, Jodhpur
taking over as

(Contd on page 2)

Year 2022 to witness two CLAT exams

(Contd from page 1)

President from the Outgoing President Prof. Faizan Mustafa.

Prof. Vijender Kumar, Vice-Chancellor, Maharashtra National Law University, Nagpur was elected as the Vice-President and Prof. V.C. Vivekanandan, Vice-Chancellor, Hidayatullah National Law University, Raipur was elected as CLAT Convenor, 2022.

The Consortium further resolved to reduce the counselling fee from 50,000/- to Rs.30,000/- for the General category candidates and Rs.20,000/- for ST/SC/OBC/BC/EWS/PWD and other reservation candidates.

In order to fully protect the privacy of candidates, the Consortium resolved to secure the consent of candidates prior to sharing any personal information with any University or any other third party, informs the letter duly signed by Prof. (Dr) Sudhir Krishnaswamy, Secretary - Treasurer, Consortium of National Law Universities.

MNLU organises webinar on radicalisation, terrorism and role of law

■ Staff Reporter

THE Internal Quality Assurance Cell (IQAC) of Maharashtra National Law University (MNLU), Nagpur, held a national webinar on 'Combating Terrorism, Insurgency, Radicalisation: The Role of Law' recently. Lt Gen (Dr) D B Shekatkar, PVSM, AVSM, VSM (retd) virtually addressed the webinar that was organised under the guidance of Prof (Dr) Vijender Kumar, Vice-Chancellor of MNLU, Nagpur.

Lt Gen (retd) Shekatkar stated that radicalisation of mind was definitely a big challenge of the world. He cited the example of 9/11 incident. However, he said that no one was born with bomb. It is some people in the society with their vested interest who radicalise innocent youths to take to arms and become terrorist. "To stop terrorism, we need to keep a strict watch on people who encourage terrorism. Youngsters today are so talented that if they get a proper mindset, they can be best resource for the nation and take the nation

to higher levels," he observed.

Addressing the students, the highly decorated veteran officer said that when a job was given to one, one must do it well. More knowledge one had, more powerful one would be. One having control over one's five senses can achieve success and reach to great heights, he said. He concluded his speech by saying, "If we love our motherland, we must always say that Bharat will live on whether we exist or not."

At the outset, Prof Dr Vijender Kumar introduced the University and welcomed the guests. Prof V P Tiwari, Co-ordinator of the programme, introduced the chief guest and proposed a vote of thanks.

The programme was attended by participants from all over the country including faculties, judges, advocates, academicians, bureaucrats, students, and members from civil society. Professors Ragini Kubhalkar, Manish Yadav, Madhukar Sharma, Nitu Kumari, Jagdish Khobragade, Sumit Malviya, Ramesh Kumar and others attended the event from MNLU, Nagpur.

MNLU, MSSB conduct intl webinar on benefit sharing



Maharashtra National Law University (MNLU) in collaboration with **Maharashtra State Biodiversity Board (MSBB)** conducted two-day international webinar on 'Access and benefit sharing: Sustaining Indian

biodiversity' recently. **Shriram Panchu** was the guest of honour of valedictory programme. Another guest **VB Mathur**, chairman of National Biodiversity Authority, apprised the gathering about the issues of multiple interpretations, difficulties in implementation of the **Biological Diversity Act 2002**, dangers of biopiracy, challenge to traditional knowledge among other issues. The chief guest in absentia, **Aditya Thackeray**, state minister of tourism, communicated a message that Maharashtra has become the only state to have been conferred with '**Inspiring Regional Leadership Award**' for Climate Action at 2021 United Nations Climate Change Conference (COP26). **Prof Vijender Kumar**, vice-chancellor of **MNLU**, and **Pravin Shrivastava**, member secretary of MSBB, also spoke on the occasion. **Trishla Dubey** proposed a vote of thanks. Himanshu Pandey, **Sopan Shinde**, Divita Pagey and **KP Rajesh** comprised the organizing team with Dubey.

MNLU, MSSB conduct intl webinar on benefit sharing



Maharashtra National Law University (MNLU) in collaboration with **Maharashtra State Biodiversity Board (MSBB)** conducted two-day international webinar on 'Access and benefit sharing: Sustaining Indian

biodiversity' recently. **Shriram Panchu** was the guest of honour of valedictory programme. Another guest **VB Mathur**, chairman of National Biodiversity Authority, apprised the gathering about the issues of multiple interpretations, difficulties in implementation of the **Biological Diversity Act 2002**, dangers of biopiracy, challenge to traditional knowledge among other issues. The chief guest in absentia, **Aditya Thackeray**, state minister of tourism, communicated a message that Maharashtra has become the only state to have been conferred with '**Inspiring Regional Leadership Award**' for Climate Action at 2021 United Nations Climate Change Conference (COP26). **Prof Vijender Kumar**, vice-chancellor of **MNLU**, and **Pravin Shrivastava**, member secretary of MSBB, also spoke on the occasion. **Trishla Dubey** proposed a vote of thanks. Himanshu Pandey, **Sopan Shinde**, Divita Pagey and **KP Rajesh** comprised the organizing team with Dubey.

3.
• द
ब्य
रो
सु
लि
अं
क
सु
के
नि
क

वें
फि
ए
स
मं
स
अं
पर
ले
पर
बा
ले
को
ब
स
ने
यु
हम
म

- ल्यूरो | मुंबई



प्रदेश सरकार के कौशल्य विकास, रोजगार व उद्यमिता विभाग के अधीन वाले दो संस्थाओं महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडल (बोर्ड) व महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद का विलय करके महाराष्ट्र राज्य कौशल्य, व्यवसाय शिक्षण (शिक्षा) व प्रशिक्षण मंडल स्थापित किया जाएगा। बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले को मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार स्कूली शिक्षा के साथ कौशल शिक्षा का पाठ्यक्रम शुरू किया जा सकेगा।

कृषि उत्पन्न विपणन अधिनियम में संशोधन
प्रदेश की बाजार समितियों (कृषि मंडियों) को मजबूत करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न विपणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत जो बहु-उद्देशीय सहकारी संस्था अपने सदस्यों को फसल कर्ज वितरित करती हैं उन्हें ही बाजार समिति के निदेशक के चुनाव में मतदान का अधिकार होगा। बाजार समिति में नियुक्त किए जाने वाले गैर सरकारी प्रशासनिक मंडल में सदस्यों की संख्या 7 से ज्यादा नहीं हो सकेगी। सरकार समिति में सचिव के रूप में सहकारिता अधिकारी श्रेणी-2 से उच्च दर्जे के अधिकारी को नियुक्त कर सकती है।

प्रदेश की फोरेंसिक विज्ञान संस्था से फोरेंसिक साइंस में स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले 150 विद्यार्थियों को हर साल इंटरन के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को राज्य के फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशालय के अधीनस्थ विभिन्न प्रयोगशालाओं में एक वर्ष का इंटरनीशिप करने के लिए स्टायपेंड भी दिया जाएगा। स्नातक के विद्यार्थियों को प्रति महीने 10 हजार और स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को हर माह 15 हजार रुपये विद्यावेतन के तौर पर दिए जाएंगे। नागपुर, औरंगाबाद और मुंबई में सरकारी फोरेंसिक विज्ञान संस्था हैं।



Govt approves Rs 95 cr to MNLU for hostel buildings

(Contd from page 1)

construction work of the University at Waranga. In March 2021 we got administrative approval but financial support was vital. The High Power Committee went through the details and gave financial approval. It is a great relief for us. We are grateful to Government of Maharashtra, Chief Minister Uddhav Thackeray, Finance Minister Ajit Pawar, Guardian Minister Dr Nitin Raut, Higher and Technical Education Minister Uday Samant for this decision."

For the last three months the issue was pending and now MNLU got the great relief. There will be twin hostel buildings that will accommodate 700 students with 350 students in each building.

Apart from hostels and residential quarters, there will be a bank whose services can be utilised by Indian Institute of Information Technology (IIIT-N), part of Kavikulguru Kalidas Sanskrit University (KKSU), people from nearby villages.

At Mauja Waranga, 60 acres of land was already allotted for this purpose.

Forensic Science UG, PG students to get internship with stipend

■ Home Minister Dilip Walse-Patil had first come up with the idea

■ Principal Correspondent

THE Maharashtra Cabinet, on Wednesday, decided to start internship with stipend at Forensic Science Laboratory for Under Graduate and Post Graduate students studying in Government Institutes of Forensic Science.

Dilip Walse-Patil, the Maharashtra Home Minister, who during his visit to Forensic Science Laboratory at Nagpur, had expressed that he wanted students studying Forensic Science to get jobs. He also had discussed the idea of providing internship to UG, PG students with stipend. The Home Department later on submitted a proposal to the Government. Acting quickly on

Govt approves Rs 95 crore to MNLU for hostel buildings

THE Maharashtra Cabinet, on Wednesday, has given approval to provide fund to the tune of Rs 95.15 crore to Maharashtra National Law University at Nagpur. Out of this fund, the university will construct hostel and residential houses on the land of University at Mauja Waranga.

While talking to 'The Hitavada', Dr Vijender Kumar, Vice-Chancellor of MNLU at Nagpur, said, "The students' hostels and some residential quarters are the part of first phase
(Contd on page 2)

the proposal, Cabinet announced it on Wednesday.

As per the decision, 150 UG and PG forensic science students from the State's forensic science institutes will be hired as interns on scholarships for a period of one year every year in various laboratories in the State under the Directorate of Forensic Science Laboratories.

At present, there are three forensic science institutes being run by State Government at Mumbai, Aurangabad and Nagpur. Walse-Patil had thought that there were not enough employment opportunities for Forensic Science graduates, the internships can be a great opportunity as the students would have hands-on experience. For the

internship purposes, the coordination between Government institutes and forensic science laboratories will be established.

The UG students will get Rs 10,000 per month and PG students will get Rs 15,000 per month stipend during the internship period of one year. Students will be recommended annually by three forensic science institutes in the state. These students will be under the control of the Director General (Judicial and Technical). Students selected for internship will be required to carry out the duties and responsibilities assigned to the posts of Scientific Assistant (Group-C) and Scientific Assistant (Cyber Crime) (Group-C) in Forensic Science Laboratories. Students will be awarded a certificate from Directorate of Forensic Science Laboratories for completing internship successfully.

MNLU organises National webinar on 'Law of Evidence: Indic Perspectives'

■ Staff Reporter

INTERNAL Quality Assurance Cell of Maharashtra National Law University (MNLU), Nagpur, organised a national webinar on 'Law of Evidence: Indic Perspectives' recently.

Prof Dr Madhusudan Penna, Professor and Dean, Department of Indian Philosophy, Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek, virtually addressed the webinar organised under the guidance of Prof Dr Vijender Kumar, Vice-Chancellor of MNLU, Nagpur.

Prof Penna stated that people knew about the contribution from all parts of the world but most often neglected the contribution of India. Indians should know about the contribution of ancestors. Britishers brought Indian Evidence Act late in 19th Century. However, he pointed out, in India, even during the Vedic times there was a widespread assertion that the truth should prevail and facts must be verified. This belief is very well articulated in texts of Jainism and Buddhism.

Prof Penna elaborated upon the Indic perspectives of Law of

Evidence. He focused upon the judicial inquiries into truth that involved adjudicative fact-finding for the purposes of justice dispensation. He remarked that the philosophical foundations of Law of Evidence could be traced to Indic knowledge systems. He enlightened the audience about methods of gauging the strength of evidence by application of parameters from the 'Pramaana Shaastra'. The parameters of validity laid down in Indic knowledge systems for perception, inference, comparison, and verbal testimony as independent sources of knowledge were discussed in detail. He shed light on the theories of comparison or 'Anumaan Pramaanam' potent with parameters to supplement doctrine of 'stare decisis', analysis of evidence and other aspects of investigations.

The eminent scholar discussed the concept of verbal testimony as dealt with in 'Nyaayashaastra' as not just a source of facts but also as a concept laying down parameters for receiving oral evidence of all types. The qualifying factors of 'Akaanksha', 'Sannidhi', 'Yogyataa Taatparya' etc were discussed in

light of linguistic understanding of the testimony.

Prof Penna dedicated ample time to explaining the utility of 'Vaada-Vidhi' or method and structure of argumentation propounded by 'Nyaayashaastra' in the process of proving or disproving the facts. Speaking of inductive and deductive logic, he made a presentation of the five-member syllogism of 'Nyaaya' vis-à-vis Aristotlian three-member syllogism, and highlighted the importance of various steps for effective argumentation. He emphasised that if these theories of epistemology, linguistics etc from Indic knowledge systems were mined and gathered for evidence laws, the law would be supplemented with strong and well-aligned multi-disciplinary approach towards justice dispensation. The programme was attended by judges, advocates, academicians, bureaucrats, students, and members from civil society from across the country. At the outset, Dr Ramesh Kumar introduced the eminent speaker. Prof Dr V P Tiwari, Co-ordinator of the event, welcomed the guests and proposed a vote of thanks.

MNLU concludes on-line faculty devpt programme on IPR

■ Programme consisted of 22 interactive sessions spread over seven days
■ More than 21 experts from eminent institutions in respective fields addressed the participants on various facets of Intellectual Property Rights

■ Staff Reporter

THE on-line Faculty Development Programme (FDP) on Intellectual Property Rights (Advance Learning) organised by Centre for Intellectual Property Rights and DPIIT-IPR Chair at Maharashtra National Law University (MNLU), Nagpur concluded recently.

Prof Dr Vijender Kumar, Vice-Chancellor, MNLU, Nagpur congratulated the participants for successfully completing the FDP with the aim of contributing to 'Aatmanirbhar Bharat' mission. He said, "FDPs are a boon to the academia. These are needed for understanding the IPR Jurisprudence."

The one-week course was designed for training and orienting the faculties from various disciplines of higher education institutions from all over India on emerging issues in Intellectual Property Rights (IPR) regime. Dr Ragini P Khubalkar, Centre head and Chair Professor, stated that the aim of FDP was to sensitise the teachers with new fields and to help them tackle the emerging complex issues while teaching.

The programme consisted of 22 interactive sessions spread over seven days. More than 21

experts from eminent institutions in respective fields addressed the participants on various facets of IPR. Prof Dr Manoj Kumar Sinha, Director, Indian Law Institute, Delhi spoke on interface between Intellectual Property and Human Rights. Prof Dr SP Rathor, Gujarat University, spoke on Traditional Knowledge Bio-piracy and IPR conflicts. He highlighted the areas of research in the field of biotechnology and agriculture to the participants.

Prof Dr Sreenivasulu NS, NUJS, Kolkata explained the celebrity rights and importance of copyright protection in entertainment industry. Prof Dr VK Unni, Indian Institute of Management, Kolkata spoke on issues related to jurisdiction and regulatory framework involved in Cyber-IP Issue. Prof Dr Alka Chawla, University of Delhi, highlighted the drawbacks and guidelines for plagiarism in education sector. Prof Dr

Lisa P Lukose, Professor of Law, GGSIPU, School of Law and Legal Studies, New Delhi, elucidated on International Framework on IPR.

Dr Raman Mittal, Professor of Law, University of Delhi, explained Emerging Trends of IPR and Trademark issues in India. He highlighted the criteria for determining well-known trademarks. Dr Dayananda Murthy, Associate Professor of Law, DSNLU, Visakhapatnam, shed light on the role of IPR in start-ups and its impact on Indian economy. Dr Nandini CP, Associate Professor of Law, DSNLU, Visakhapatnam; Dr Amol Karwa, Assistant Professor of Law, Narayanrao Chavan Law College, Nanded; Dr Vandana Mahalwar, Assistant Professor of Law, University of Delhi; Debmita Mondal, Assistant Professor of Law, HNLU, Raipur; Abhijeet Rohi, Assistant, Professor of Law,

MNLU, Mumbai, illustrated various issues related to Indian IPR regime.

Dr Pankaj Borker, Deputy Controller of Patent & Design, IPO, Mumbai, Team Leader, RGNIPM, Nagpur, discussed patent registration process in detail. Chirag Tanna, Director, Patent & Trademarks at INK IDEE, (India, Singapore) Partner, IPR at Eight Mercatus, spoke on Medical Devices IPR Strategies & Patentability of Software Inventions. Damodar Vaidya, Executive Partner, Lakshmi Kumaran and Sridharan, Pune explained intricate relation between taxation of IPR and digital economy.

The programme was conducted online due to COVID-19 situation. Shweta Kulkarni and Dr Anchit Verma, Research Assistants with DPIIT-IPR Chair, worked for success of the programme.

‘फॉरेन्सिक’च्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन स्वअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील न्यायसहायक विज्ञान संस्थांमधून फॉरेन्सिक सायन्स पदवी व पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयांतर्गतच्या विविध प्रयोगशाळांमध्ये प्रतिवर्षी १५० विद्यार्थ्यांना एक वर्ष कालावधीसाठी विद्यावेतनावर इंटर्न म्हणून घेण्यात येणार आहे.

मंत्रिमंडळाने हा निर्णय बुधवारी घेतला. मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था कार्यरत आहेत. तेथे बी. एस्सी व एम. एस्सी (फॉरेन्सिक सायन्स) पदवी प्राप्त विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या संधी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसल्याने न्यायसहायक विज्ञान संस्था व न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा यांच्यामध्ये समन्वय निर्माण करून प्रतिवर्षी न्यायसहायक विज्ञान संस्थांमधील पदवी व पदव्युत्तर पदवी उत्तीर्ण १५० विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप उपलब्ध करून देण्यात येईल.

एका वर्षाच्या इंटर्नशिप कालावधीत प्रतिमाह अनुक्रमे प्रत्येकी दहा हजार व पंधरा हजार विद्यावेतन मिळेल. तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना इरादा पत्रासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

इरादा पत्रातील अटी व शर्तीची पूर्तता करू न शकल्यामुळे मार्च २०२० पासून पुढील एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये ज्यांचे इरादापत्र

विधी विद्यापीठासाठी नागपूरला वसतिगृह

नागपूर जिल्ह्यातील वारंगा येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठासाठीचे वसतिगृह व इतर निवासी इमारती बांधण्यासाठी ९५.१५ कोटी रुपये निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मौजा वारंगा येथे यासाठी ६० एकर जागा देण्यात आली आहे. तेथे विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने, मुलामुलीची वसतिगृहे, बँक, वाहनतळ आदी सुविधा उभारण्यात येतील.

कंपनी एकत्रीकरण, शुल्क आकारणार

कंपनी एकत्रीकरण तथा विलगीकरणाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या दस्तांवर मुद्रांक शुल्काची आकारणी करण्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अशा दस्तांवर देय होणाऱ्या मुद्रांक शुल्काची वसुली होऊन शासनाच्या महसुलामध्ये वाढ होणार आहे.

कार्यान्वित होते त्यांना ९ महिन्यांचा भरपाई कालावधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

वकिली हा पेशा नव्हे, उत्तरदायित्व -न्या. गवई

डॉ. पंजाबराव देशमुख विधी
महाविद्यालयाचा अमृतमहोत्सव

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अमरावती : मूलभूत हक्कांच्या



जपणुकीबरोबरच
सामाजिक व
आर्थिक
न्यायाची
प्रस्थापना, तसेच
जनसामान्यांचे

हित साधले जाणे हे संविधानाच्या
निर्मात्यांच्या विचारांचे सूत्र होते.
मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे
यांचा मेळ घालणे राज्यघटनेला
अभिप्रेत आहे. वकिली हा केवळ
उपजिविका किंवा उत्पन्न
मिळवण्याचा मार्ग नव्हे, तर
सामाजिक उत्तरदायित्वही त्यातून
जोपासले गेले पाहिजे. ही जाणीव
वकिली व्यवसायात विद्यार्थ्यांनी
अंगीकारणे आवश्यक आहे, असे
प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे
न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी
रविवारी येथे केले.

येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख
विधी महाविद्यालयाच्या अमृत
महोत्सवानिमित्त माजी विद्यार्थी
संमेलन व विस्तारित इमारत
बांधकामाचे भूमिपूजन न्यायमूर्ती
भूषण गवई व पालकमंत्री अॅड.
यशोमती ठाकूर यांच्या
उपस्थितीत झाले, यावेळी ते
बोलत होते.

श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे
अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.
मंचावर न्या. विजय आचलिया,
न्या. पी. एन. देशमुख, न्या. अनिल
किलोर, छत्तीसगडचे माजी
महाधिवक्ता जुगलकिशोर
गिल्डा, जिल्हा व सत्र
न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश
रवींद्र जोशी, लंडन येथील ज्येष्ठ
अधिवक्ता साजिद शेख,
पालकमंत्री यशोमती ठाकूर,
प्राचार्य डॉ. वर्षा देशमुख आदी
उपस्थित होते. महाविद्यालयाचे
माजी विद्यार्थी न्यायमूर्ती गवई,
पालकमंत्री ठाकूर, विविध
न्यायमूर्ती, अधिवक्ता आदी
मान्यवरांचा सत्कार संस्थेतर्फे
करण्यात आला. न्यायमूर्ती गवई
म्हणाले, भाऊसाहेबांनी शेतकरी,
शेतमजूर, जनसामान्यांच्या केसेस
लढून त्यांना न्याय मिळवून दिला.
राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.
आंबेडकर व भाऊसाहेब या
दोहोंचे ध्येय एकच होते.

गोरगरीब, वंचित,
जनसामान्यांचे उन्नयन हे त्यांचे
स्वप्न होते व त्यासाठी त्यांनी
आजीवन कार्य केले. दोहोंनीही
महात्मा ज्योतिबा फुले यांना गुरू
मानून त्यांच्यापासून प्रेरणा
घेतली. प्रत्येकाने सामाजिक
उत्तरदायित्वाची जाणीव ठेवली
पाहिजे, असे आवाहनही न्या.
गवई यांनी केले.



९५ कोटी रु. महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला मंजूर

राज्य सरकारचा निर्णय : कॅम्पसचा विकास होणार

आशिष रॉय

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : संत्रानगरीतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाने कॅम्पस विकासाकरिता राज्य सरकारला १७० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला होता. दरम्यान, राज्य सरकारने विद्यापीठाला ९५ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत व उर्वरित निधी इतर माध्यमांतून प्राप्त करण्याची सूचना केली आहे.

यापूर्वी २०१८ मध्ये विद्यापीठाने २३० कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यावेळी १५० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. यासंदर्भात उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाद्वारे जारी निर्णयानुसार, नवीन ९५ कोटी रुपये विद्यार्थी व विद्यार्थिनी वसतिगृहे, सोयीसुविधा, १-बीएचके कर्मचारी क्वॉर्टर्स, प्र-कुलगुरु बंगला, कुलपती बंगला, बँक व पार्किंग सुविधेवर खर्च केले जाईल.

याशिवाय, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, विद्युतीकरण व एसटीपी यावरही काही रक्कम खर्च होईल. उर्वरित ७५ कोटी रुपये इतर माध्यमांतून मिळविले

स्वतःचे कॅम्पस नाही

हे विद्यापीठ २०१६ मध्ये कार्यान्वित झाले; परंतु विद्यापीठाकडे अद्याप स्वतःचे कॅम्पस नाही. याकरिता, मिहानमधील इमारत भाड्याने घेण्यात आली आहे. प्रशासकीय कार्यालये नुकतीच स्वतःच्या जागेत स्थानांतरित झाली.

जाणार आहेत. त्यासाठी सीएसआर निधी व खासगी देणगीदात्यांवर भर दिला जाईल. आधीचे १५० कोटी रुपये ग्रंथालय, शैक्षणिक खोल्या, प्रशासकीय खोल्या, संरक्षण भिंत, मुख्य प्रवेशद्वार, अंतर्गत रस्ते व कुलगुरु बंगल्याकरिता खर्च करण्यात आले आहेत. या विद्यापीठात बी.ए., एल.एल.बी. (ऑनर्स) अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

त्यामध्ये १२० विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. या पाचवर्षीय अभ्यासक्रमात क्लॅटमधील गुणांच्या आधारे प्रवेश दिला जातो. याशिवाय येथे एलएलएम व पीएच.डी.ही उपलब्ध आहे.